अध्यक्ष महोदय

सत्यमेव जयते

असंशोधित

13 JUL 2000

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग २–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर रहित)

बि० स० मु० (एल० ए०) 116—मोनो—1,000—10-3-2000—

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सी0 बी0 आई0 छापा मारेगी तो उसका उत्तर सरकार देगी ?

(व्यवधान)

आपलोग कैसे बोल रहे हैं । आप बैठिये । सामान्य प्रशासन पर आपलोग बोलियेगा । बैठिये ।

(व्यवधान)

वित्तीय कार्य। प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग अपनी माँग प्रस्तुत करें ।

वित्तीय कार्य

डा0 रामचंद्र पूर्वे (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संबंध में 31 ~~xx~~ मार्च, 2001 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये 7,35,07,000 (सात करोड़, पैंतीस लाख, सात हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव ~~xxxxx~~ राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस पर जनरल नेचर के जो कटौती प्रस्ताव हैं, जिस पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं, मैं उसको लेता हूँ । इसमें सर्वश्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंजीत कुमार सिंह, मृगेन्द्र प्रताप सिंह, भोला प्रसाद सिंह, रामसेवक हजारी, विनोद कुमार सिंह, राम नरेश राम एवं प्रेम कुमार ~~xxxxx~~/ का कटौती प्रस्ताव क्रमांक 411 से 419 व्यापक है । माननीय सदस्य, श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव मूव करें ।

श्री नवीन किशोर प्रसाद सिंहा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस शीर्षक की माँग 10 रूपये से ~~xxx~~ घटायी जाय, राज्य सरकार की मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय नीति पर विचार विमर्श करने के लिए ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे दल की ओर से माननीय सदस्य, नंद किशोर यादवजी विचार रखेंगे ।

अध्यक्ष : श्री नंद किशोर यादवजी ।

(व्यवधान)

मिल जायेगा, बंट जायेगा । बंटवा दीजिये ।

श्री नंद किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। आज का जो विषय है, सच पूछिये तो बिहार के गांव-गांव तक जो विकास तंत्र फैला है, जो सरकार की मशीनरी फैली है, उस पूरी मशीनरी का जो हृदय है, वह इस राज्य का सचिवालय है और हृदय तंत्र के तार जब झंकृत होते हैं तो उस झंकार की गूँज गांव-गांव तक पहुंचती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना आपसे यह चाहता हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये न। सब पर नियंत्रण है। आप (नवीन किशोर प्र० सिन्हा) भी अपने पर नियंत्रण कीजिये।

श्री नंद किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, जो राज्य का हृदय है, उसके धड़कने की गति बदल गयी है और गति बदलने के कारण जो हृदय की धड़कन शरीर में प्राण का संचार करती है, धड़कन की गति बदलने के कारण वहां अब पेस मेकर लगाने की आवश्यकता पड़ गयी है। जो मंत्रिमंडल काम कर रहा है, उसके चित्र में दस साल में जो फर्क आया है, उसका थोड़ा सा नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि आज राज्य की आबादी दस करोड़ से भी अधिक हो गयी है। आपको जान कर आश्चर्य होगा कि इस दस करोड़ की आबादी में 37 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनको पीने का शुद्ध पानी नसीब नहीं है, बिजली नसीब नहीं है, जिसके मूल गांव के अन्दर विकास की कोई किरण पहुंच नहीं पायी है। ऐसे 37 प्रतिशत बिहार के लोग इस प्रकार की त्रासदी झेलने के लिये विवश हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर 38 जिले बिहार के ऐसे हैं जो देश के 100 पिछड़े जिलों में गिने जाते हैं। उससे आगे बढ़ें आप तो यह दिखायी पड़ेगा कि बिहार के अन्दर जिन कारनामों की बराबर बात की जाती थी।

(इस अवसर पर पीठासीन पदाधिकारी, श्री गणेश प्रसाद यादव ने आसन ग्रहण किया)

बिहार का वर्तमान मंत्रिमंडल जिन कारणों से अपनी पहचान बनाने की 10 साल से कोशिश लगातार करता रहा है, उस मंत्रिमंडल के द्वारा लिये गये निर्णय इस राज्य में लागू नहीं होते हैं। सरकार के द्वारा की गयी घोषणाएं ~~XX~~ केवल कागज के पन्नों में सिमट कर रह जाती हैं और अध्यक्ष महोदय, सबसे दुखद पहलू यह है कि सरकार जिन चीजों से अपनी छवि बनाने की कोशिश करती है सरकार ने लगातार ~~XXX~~ कोशिश मीडिया के माध्यम से, अपने मुखिया की घोषणा के माध्यम से और तो और हरिजनों के घरों में जा कर उनके बच्चों को साबुन से नहला कर जो मैसेज

(61)

टर्न-24ए/13.7.2000/
श्रीरमण/

देने की सरकार ने कोशिश करनी चाही, यह मैसेज था कि सरकार गरीबों की रहनुमाई करनेवाली सरकार है और सरकार के मुखिया के द्वारा भी सरकार ने मैसेज दिया कि गरीबों ~~की/के~~ का हित सोचती है, गरीबों के कल्याण के लिये काम करनेवाली सरकार गरीबों के आंसू पोछना चाहती है । सत्तारूढ़ दल के मुखिया ने एक विशेष भाषा का प्रयोग करके यह मैसेज देने का काम किया था कि गांव के विकास के लिये प्रतिबद्ध सरकार है यह ।

~~सभा~~ महोदय, आज जो मेरा भाषण है, आज की बात है, केवल सरकार की आलोचना के लिये नहीं है । मैं अपने विचार ~~के/~~ के माध्यम से केवल आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि सरकार को उसका चेहरा दिखाना चाहता हूँ, एक आईना का प्रयोग करना चाहता ~~है~~ हूँ कि सरकार अपने चेहरे को देखे, अपने भयानक चेहरे को देखे ।

~~सभा~~ महोदय, सरकार ने घोषणा के अनुरूप काम नहीं किया । मैं बात छोटी ~~से~~ शुरू करता हूँ । बार-बार कहा है मैंने गरीबी उन्मूलन योजनाओं के बारे में, गरीबों की रहनुमाई के बारे में और गरीब का बेटा, चपरासी का भाई राजा की कुर्सी पर बैठने के बाद गरीबों के हितों की चिंता करेगा । मैं यह कहूँगा कि बिहार के अन्दर गरीबों के आंसू पोछने का काम ~~करेगी~~ यह सरकार करेगी ?

सभापति महोदय, आप जानते हैं केन्द्र की सरकार ने देश भर के गरीबों के लिये आधी कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने के लिये लालकार्ड योजना जारी की थी, मुझे बड़ी उम्मीद थी, मैं तो 1995 में एम०एल०ए० बना हूँ और आप जानते हैं कि विधायक बनने के बाद मेरे मन के अन्दर यह भाव जगा था कि विधायक बनने के बाद क्षेत्र का विकास, गरीबों के हितों के लिये काम करूंगा । सरकार बार-बार घोषणा करती थी तो विधान सभा के अन्दर जा कर अपनी बात कह कर गरीबों की भलाई की बात करूंगा, लेकिन ~~मैं~~ मैंने कहा आपसे सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना को लागू करने के लिये आधे दाम पर अनाज के लिये लाल कार्ड प्रारंभ किया था । मुझे यह उम्मीद थी कि गरीबों की बराबर बात करनेवाली सरकार इस प्रदेश के अन्दर,

केन्द्र-श्री महतो   (व्यवधान)

केन्द्र की सरकार की बात कर रहा हूँ । अगर मैं यहां बता दूँगा तो और मुसीबत में फंस जायेंगे । लालूजी, यहां मत बोलिये । आप कितने तेज हैं, यह मुझे पता है । आपसे सीखने की मुझे आवश्यकता नहीं है । मुझे आपसे अक्ल लेने की आवश्यकता नहीं है ।

टर्न-24ए/XX 13.7.2000/ (62)

श्रीरमण/

सभापति(श्री गणेश प्रसाद यादव) : माननीय सदस्य, आसन की तरफ मुखातिब होकर बोलें ।

श्री नंद किशोर यादव : सभापति महोदय, दूसरे सदस्यों को भी कहिये आप कि टोकाटोकी बन्द करें ।

सभापति महोदय, इस बात से हम चुप नहीं होनेवाले हैं । टोकाटोकी से नंद किशोर यादव चुप होनेवाला नहीं है, ध्यान रखियेगा इस बात का ।

(व्यवधान)

आपने जा कर नुक्कड़ सभाएं की हैं, तब भी हम जीत कर आये हैं । आपकी मेहरबानी से नहीं ~~XX~~ आये हैं जीत कर ।

सभापति(श्री गणेश प्रसाद यादव) : माननीय सदस्य, आप अपनी बातों को रखिये ।

श्री नंद किशोर यादव : सभापति महोदय, नुक्कड़ सभाएं की वहां जाकर इन्होंने ।

...क्रमशः...

टर्न -25/राहुल/13.7.2000

श्री नन्द किशोर यादवः (क्रमशः) पूर्वे जी भले मेरी मदद किए होंगे, आपने नहीं किया ।

सभापति महोदय, मैं कह रहा था आपसे कि केन्द्र सरकार ने लाल कार्ड योजना जारी की और जब योजना जारी हुई तो मुझे लगा था कि बिहार के अंदर जो सरकार बार-बार गरीबों की रहनुमाई की बात करती है, वह सरकार बिहार में लाल-कार्ड योजना को पूरी तरह से लागू करेगी और मुझे विश्वास था, मैं सच कहूंगा, विरोधी पार्टी का कार्यकर्त्ता होने के बावजूद भी मैं सरकार की घोषणा के भंवरजाल में फंस गया था । मुझे उम्मीद बन गयी थी कि गरीबों की रहनुमाई करने वाली सरकार शायद बिहार में लाल कार्ड योजना को जारी करेगी । लेकिन, सभापति महोदय, यह विधान-सभा इस बात का गवाह है कि सरकार ने घोषणा की थी और सरकार ने इस बात की जानकारी दी थी कि बिहार में 84.25 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं । लेकिन इस सरकार ने आज इतने साल बीत जाने के बाद भी केवल 8.90 लाख परिवारों को लाल कार्ड वितरित किया है । यह आंकड़ा मेरा नहीं है । यह आंकड़ा बिहार सरकार का है । मैं केवल आपसे यह कहना चाहता हूं गरीब की रहनुमाई की बात करने वाली सरकार, जो यहां काम कर रही है बिहार में, उस सरकार ने केन्द्र सरकार से मिलने वाले अनाज, केन्द्र सरकार से योजना आने के बाद भी उस योजना को पूरी तरह लागू करने में सक्षम नहीं हो सकी, असफल सिद्ध हो गयी और केवल इतना ही नहीं, लाल कार्ड कितना जारी हुआ ? सबसे ज्यादा दुःख की बात तो यह है कि केन्द्र से जो अनाज गरीबों के लिए आता था, जिनको दो जून खाना नसीब नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, उन गरीबों के लिए जो अनाज आया था, उस अनाज को सरकार ने गरीबों में बांटने के बजाए काले बाजार में बेचने का काम किया है ।

सभापति महोदय, लाल कार्ड योजना के बारे में यहां चर्चा विस्तार से हुई है । लगातार, रोज होती है और उन सब बातों को मैं दुहराना नहीं चाहता हूं । मैं केवल

टर्न-25/राहुल/12. 7. 2000

आपसे यह कहना चाहता हूं कि सरकार अपने चेहरे को देखने की कोशिश करे, अपने चरित्र को देखने की कोशिश करे और इस बात का अहसास करे कि आपकी घोषणाओं का क्रियान्वयन कितना हो रहा है । आज इन योजनाओं का लाभ गांवों में रहने वालों को नहीं मिल रहा है । जिन गांव के लोगों ने आपको झोली भर-भर करवोट डालने का काम किया था उनगरीबों का पेट भरने एवं हक बचाने के बजाए आपने अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए अपने मंत्रिमंडल की कार्यक्षमता को छिपाने के लिए, जिस मंत्रिमंडल में कार्यक्षमता नहीं है, उसको छुपाने के लिए उन गरीबों केराशन को खाने का काम किया है ।

सभापति महोदय, गरीबी उन्मूलन की योजना यह नहीं है । आपको याद होगा कि आज केन्द्र सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है जिन योजनाओं के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को उठाने की बात चलती है और मैंने आपसे कहा कि सच्चाई यह है कि गरीबों की रहनुमाई करने वाली सरकार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कमी करने में सक्षम नहीं है । देश भर में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का औसत अगर 29 प्रतिशत है तो बिहार के अंदर गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का औसत उससे कम हो ना चाहिए क्योंकि यहां की सरकार गरीबों की रहनुमाई करने वाली सरकार है लेकिन सभापति महोदय, आज सारा प्रदेश यह जानता है कि उस समय 1988 के आसपास इस बिहार के अंदर गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या मात्र 40.8 लाख थी तो आज गरीबों की रहनुमाई करने वाली सरकार के कार्यकाल में, दस साल में इस प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ कर 56 प्रतिशत से अधिक हो गयी है ।

सभापति महोदय, यह संख्या केवल इसलिए बढ़ती गई, कौन सा कारण है कि यह संख्या बढ़ती चली जा रही है जबकि इस प्रदेश के लिए भी केन्द्र सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए, ग्राम समृद्धि के लिए प्रत्येक साल दो हजार करोड़ रुपए लगातार इस प्रदेश को भेजने का काम करती रही है । दो हजार करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने का कारण क्या है ?

क्रमशः

टर्न-26/मधुप/13.7.2000

श्री नंद किशोर यादव : (क्रमश:)- महोदय, आज इसके लिये गहराई में जाने की आवश्यकता है, छानबीन करने की आवश्यकता है । महोदय, आपको यह बात दिखाई पड़ेगी कि वर्त्तमान सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं के, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के पैसे का उपयोग नहीं कर पायी है इस बिहार के अन्दर । जिसका परिणाम आपको दिखाई पड़ रहा है । महोदय, आप याद करें, आपको ध्यान में होगा, जवाहर रोजगार योजना, महोदय, आपके ध्यान में होगा ग्राम समृद्धि योजना, आपके ध्यान में होगा, बाल विकास परियोजना, कई एक ऐसी योजनायें, जिन योजनाओं के माध्यम से केन्द्र सरकार की यह मंशा थी कि गाँव के अन्दर रहने वाले गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाया जाय । महोदय, ग्राम समृद्धि योजना के लिये लगातार पैसा आ रहा है, प्रत्येक साल पैसा आ रहा है । ग्राम पंचायत चुनाव के विवाद के कारण भले ही पैसे में कुछ कटौती होगी लेकिन पैसे लगातार आ रहे थे । आज इसपर विचार करने की जरूरत है । ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 के आवंटन को देखा जाय, 522.28 करोड़ रूपया और सरकार ने केवल 356.24 करोड़ रूपया ही इसमें से खर्च किया । महोदय, यह वह पैसा है जिन पैसों के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुँचाया जाना था, इस पैसे में 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार देती है और 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को देना पड़ता है और इस पैसे के उपयोग का केवल एक आधार बनाया गया कि इन पैसों के माध्यम से गाँव के अन्दर रहने वाले बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा, गाँव के अन्दर विकास की किरणें फूटेंगी, गाँव के अन्दर रहने वाले बेरोजगार को रोजगार मिलेगा । लेकिन राज्य सरकार यह राशि खर्च नहीं कर पायी । महोदय, ये जो गरीबी उन्मूलन की योजनायें हैं, गरीबी-रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के स्तर को ऊँचा उठाने की योजनायें थीं, उन योजनाओं के

पैसे को भी इस सरकार ने पूरा खर्च करने का काम नहीं किया है ।

सभापति महोदय, केवल इतना ही नहीं कहना चाहता हूँ, यहाँ इन्दिरा आवास योजना की बात बड़े जोरों से होती है, सरकार बार-बार कहती है कि गरीबों के लिये पक्का मकान बनायेंगे ।

॥ पीली पत्ती ॥

सभापति महोदय, मुझे कितना बोलना है ? अपनी पार्टी की ओर से मैं अकेले आज बोलने वाला हूँ ।

सभापति ॥श्री गणेश प्रसाद यादव॥ : आपको 15 मिनट बोलना है । आपने 2.02 बजे से बोलना शुरू किया है ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, अभी 15 मिनट तो नहीं हुआ है, अभी तो मैंने शुरू ही किया है । महोदय, आप जितना कहेंगे, मैं उतना ही बोलूँगा ।

सभापति ॥श्री गणेश प्रसाद यादव॥ : ठीक है ।

श्री नंद किशोर यादव : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि सरकार ने बड़े जोर-शोर से घोषणा की कि प्रत्येक गरीबों के लिये पक्का मकान बनाया जायेगा । महोदय, वर्तमान मुख्यमंत्री जी जब घोषणा करती थीं तो मुझे इस बात की खुशी होती थी, वे सुशील मोदी जी की बहन हो सकती हैं लेकिन लालू जी तो मेरे भाई हैं, जो भी मेरे रिश्ते में लगती होंगी, लेकिन जब भी वे घोषणा करती थीं तो मुझे खुशी होती थी कि कम से कम मेरे परिवार का एक सदस्य गरीबों के लिये पक्का मकान बनवाने की घोषणा कर रहा है ।

॥ व्यवधान ॥

लालू जी मेरे भाई हैं, उनसे आप मेरे रिश्ते को पूछ लीजियेगा । सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि जब मेरे बड़े भाई के परिवार के लोग यह घोषणा कर रहे थे कि गरीबों के लिये पक्का मकान बनाया जायेगा तो मुझे खुशी होती थी कि कम से कम एक महिला मुख्यमंत्री बिहार के प्रत्येक

गरीबों के लिये पक्का मकान बनाने की घोषणा कर रही हैं लेकिन सभापति महोदय, इस घोषणा का आज तक क्या हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ ? आज गरीब टकटकी लगाकर आसमान की ओर देख रहा है, देख रहा है इस सरकार के मंत्रियों की ओर, आज गरीब सरकार के पदाधिकारियों की ओर देख रहा है कि कब कोई आयेगा, उनके झोपड़ी को पक्का मकान बनवायेगा, उनके रहने के लिये सर के ऊपर छत आयेगा लेकिन वह गरीब टकटकी लगाये देखता रहा और उनके पास पैसा नहीं पहुँचा । महोदय, आज 100 करोड़ रूपया से अधिक राशि इस सरकार के पास बचा हुआ है गरीबों के लिये पक्का मकान बनवाने हेतु । मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या बिहार सरकार अब यह मानती है कि बिहार के गरीबों के लिये पक्का मकान बनाने की आवश्यकता नहीं है? क्या पूरे बिहार में गरीबों के लिये पक्का मकान बन गया ?

महोदय, सरकार पैसा को खर्च नहीं कर पाती है और विधान सभा के अन्दर सरकार भाषण देगी, सरकार जवाब देगी तो मैं जानता हूँ कि सरकार यह कहेगी कि बाढ़ आ गया, दो-दो चुनाव हो गये, यह हो गया, वह हो गया, इसलिये हम पैसे को खर्च नहीं कर सके । लेकिन महोदय, सच तो यह है कि इस मंत्रिमंडल के अन्दर यह कूवत, यह ताकत, यह क्षमता नहीं है कि विकास कामों के पैसों को पूरा का पूरा विकास कार्यों में खर्च कर सके ।

महोदय, यही कारण है, चाहे वह गरीबी उन्मूलन की योजनायें हों, चाहे गरीबों के लिये पक्का मकान बनवाने का पैसा हो, लाल कार्ड योजना हो, सारी योजनाओं को सरकार निश्चित कार्यकाल के अन्दर पूरा नहीं कर पाती है ।

सभापति महोदय, कई ऐसी योजनायें हैं, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है । गरीबों की बस्ती में 107 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 128 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार ने पैसा दिया था । सभापति महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस सरकार ने गरीबों की बस्तियों में बनने वाले उन स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक स्वास्थ्य केन्द्र का भी निर्माण करने का काम इस साल नहीं किया है । पैसा लैप्स कर गया, पैसा बरबाद हो गया लेकिन एक भी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का काम इस सरकार ने नहीं किया ।

सभापति महोदय, सरकार बराबर गरीबों की बात करती है । महोदय, मैंने थोड़े उदाहरण दिये हैं, चाहें तो और उदाहरण दे सकता हूँ । लेकिन महोदय, आजकल जब मैं बोलता हूँ तो उधर से बात होगी कि फासिस्ट लोग बोल रहे हैं, साम्प्रदायिक लोग बोल रहे हैं और धर्मनिरपेक्ष लोग भाषण करते हैं तो अपने भाषण में बार-बार अल्पसंख्यक समुदाय का जिक्र करते हैं ।

(क्रमशः)-

टर्न:27:अनी:दि0 13·7·2000

(69)

...क्रमशः...

श्री नंद किशोर यादव: लेकिन सरकार ने एक साल में पैसा खर्च नहीं किया । सरकार सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने का काम करती है। नारे से। यह सरकार किस प्रकार से समाज के अन्दर विभेद पैदा करने की कोशिश कर रही थी, अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने की कोशिश करते रहे बातों के द्वारा लेकिन उस समुदाय के विकास के लिए जो साढ़े बारह करोड़ रूपये आवंटित किये थे इस सरकार ने, लेकिन इस सरकार ने उस पैसे को खर्च करने का काम नहीं किया ।

सभापति महोदय, दोपहर के भोजन का जिक्र आपके सामने है, आप जानते हैं। यह घोषणा हमने नहीं की थी, यह घोषणा सुशील मोदी ने नहीं की थी, इस सरकार ने वोट प्राप्त करने के लिए, गरीबों के आँखों में धूल झोंकने के लिए इस सरकार ने घोषणा किया था कि हम दोपहर का भोजन गरीब बच्चों को देने का काम करेंगे । इस सरकार ने घोषणा किया था कि हम प्रत्येक गरीब परिवार के बेटे को एक रूपया रोज देने का काम करेंगे । सभापति महोदय, इसका क्या हुआ हश्र ? सभापति महोदय, इस योजना का हश्र क्या हुआ, कितने गरीब के बेटे को दोपहर का भोजन नसीब हो रहा है? आंकड़े इस बात के गवाह हैं। यह सब सारी योजना कागज पर रह गई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस कार्यक्रम का 140करोड़ रूपया के अनाज का कोई अता-पता नहीं है। कहाँ चला गया अनाज, किसके खाते में चला गया और जो एक रूपया रोज स्कूलों में गरीब के बेटों को देने की बात थी, आज उस पैसे का क्या हुआ, कितने स्कूलों में पैसा मिल रहा है? आज इस बात का लेखा-जोखा इस सरकार के पास नहीं है। ये सारी योजना हवा में बनकर रह गयी है। सभापति महोदय, सच बात तो यह है कि यह सरकार दिवालिया हो गयी है। सरकार के पास जो परिसम्पत्ति है, उस परिसम्पत्ति से ज्यादा देनदारी सरकार के ऊपर हो गई, सरकार बिल्कुल कंगाल और दिवालिया घोषित कर दी गई है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि सरकार की कुल परिसम्पत्ति .....

सभापति (श्री गणेश प्रसाद यादव): माननीय सदस्य, अब आप कितना समय लेंगे ।

टर्न:27:अंजनी:दि0 13·7·2000

श्री नंद किशोर यादव: महोदय, जितना आप समय देंगे ।

सभापति[श्री गणेश प्रसाद यादव]: ——, आपको जो सुविधा हो । आप कितना समय लेंगे ।

श्री नंद किशोर यादव: महोदय, आप जितना कहेंगे । जितना मेरा आवंटित समय है, उतना मैं बोलूंगा । बोलने के लिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, बिहार सरकार की कुल परिसम्पत्ति 17हजार234·72 करोड़ की और देनदारी बढ़ गयी है 25हजार210·26 करोड़ की, सरकार दिवालिया हो गयी है महोदय । महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जो सरकार अपने कुल खर्च का केवल पाँच प्रतिशत पूंजी निर्माण के कार्य में खर्च करने का काम करती है। पूरे देश के अन्दर, दूसरे राज्य में अपने कुल खर्च का 10परसेंट, महाराष्ट्र और गुजरात 20परसेंट अपने परिसम्पत्ति के निर्माण में खर्च करता है, वहाँ बिहार केवल 5परसेंट और एक साल ऐसा हुआ जब केवल साढ़े चार परसेंट कुल खर्च का परिसम्पत्ति निर्माण में बिहार सरकार ने खर्च करने का काम किया है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार जहाँ एक तरफ बिहार के विकास के बारे में पूरी तरह से अकर्मण्य रही । जहाँ बिहार सरकार बिहारके गरीबों के कल्याण के लिए चलाये जानेवाली योजनाओं के बारे में लापरवाह रही, जानबूझकर उन योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया। मैंने आपके सामने उदाहरण दिया गरीबी उन्मूलन योजनाओं का, वही हश्र हुआ इस प्रदेश के अन्दर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याणकारी योजनाओं का, वही हश्र हुआ बाल विकास परियोजना का, वही हश्र हुआ बाकी दूसरी योजनाओं का और आज विकास के मामले में बिहार दूसरे राज्यों की तुलना में लगातार इतना पीछे हो गया, जहाँ हम इस स्थिति में खड़े हो गये हैं कि जहाँ मेरे बारे में कहा जाता है कि हम पतन के कगार पर चले गये हैं। जहाँ से केवल खाई हमारे सामने है।

(71)

टर्न:27:अनी:दि0 13·7·2000

सभापति महोदय, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, आज मैं केवल सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। बिहार अगर अवनति की ओर जा रहा है, अगर बिहार विकास के रास्ते में आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसका खामियाजा केवल सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा विपक्ष को भी भुगतना पड़ेगा, बिहार के समक्ष 10करोड़ जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ।

(क्रमशः)

श्री नन्दकिशोर यादव : (क्रमशः) मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, अब भी समय है, चेतने का काम कीजिए । आप सरकार बना सकते हैं लेकिन बिहार की जनता ने आपको नकारने का काम किया है । लेकिन आज के दौर के राजनीति के कारण आप आज सत्ता में बैठे हैं और कह सकते हैं कि हम सत्तारूढ़ पार्टी के हो गये हैं लेकिन याद रखिए, बिहार की जनता ने आपको चुनाव में नकारने का काम किया है, आपके 10 सालों के कुशासन के कारण, 10 सालों के प्रशासन के कारण । हम यह कहना चाहते हैं आपसे कि आप चेतने का काम कीजिए, सवाल इस बात का नहीं है...

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, हमको मैनडेड मिला है ।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : तो कैसे आप 160 से घटकर आप 124-125 पर पहुंच गये हैं ।

श्री नन्दकिशोर यादव : सभापति महोदय, हम कहना चाहते हैं, ठीक है इनकी सरकार बन गई है, मानते हैं इस बात को लेकिन मैं कहना चाहता हूं.....

सभापति महोदय, मेरी दोस्ती अगर लालू जी से है तो एक बड़े भाई के नाते हैं लेकिन इनसे हमारे मतभेद भी हैं । लेकिन मतभेद हमारे सिर्फ लालू प्रसाद जी से नहीं है, मेरे मतभेद श्री सुशील कुमार मोदी जी से भी है...

श्री लालू प्रसाद : आप यह बताईए कि आप हमको बड़ा भाई मानते हैं कि नहीं ?

श्री नन्दकिशोर यादव : हां, मानते हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, श्री लालू प्रसाद जी से संबंध अच्छे हैं तो मतभेद भी है । मेरा मतभेद श्री सुशील कुमार मोदी से भी कुछ सवाल पर होते हैं और मेरे मतभेद होते हैं श्री लालू प्रसाद जी के सवाल पर, श्रीमती राबड़ी देवी के सवाल पर । महोदय, श्री मोदी जी जब भाषण देते हैं तो ये बराबर कहते हैं कि ये सरकार नकारी है, सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तिफा दे दे तो मेरे

मतभेद बढ़ जाते हैं श्री सुशील कुमार मोदी जी से भी । मैं इनको समझाता हूं, डांटता हूं पार्टी के अध्यक्ष के नाते, आप क्या कर रहे हैं, आप किससे इस्तिफा की मांग कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आपकी बात श्री सुशील कुमार मोदी जी नहीं मानते हैं तो आपके पास अधिकार है .... (व्यवधान)

श्री नन्दकिशोर यादव : सभापति महोदय, मैं कह रहा था, मैं श्री मोदी जी को कहता हूं कि आप सरकार से इस्तिफा नहीं मांगे, आप गलत कर रहे हैं । मैं इनको इसलिए मना करता हूं कि जिस सरकार से आप इस्तिफा मांगते हैं, उस सरकार के सामने नैतिकता शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, नैतिकता के बारे में क्या कह रहे हैं, सरकार यह नहीं जानती है ।

श्रीमती राबड़ी देवी (मुख्य मंत्री) : हम आपसे पूछना चाहते हैं, देश में जो हो रहा है, राज्य में जो हत्यायें हो रही हैं । क्या सारे पार्टी के लोग लिखकर देंगे कि कहीं हत्या नहीं होगी, कहीं चोरी नहीं होगी, कहीं डकैती नहीं होगी, कहीं लूट-मार नहीं होगी, कहीं बलात्कार नहीं होगा, कहीं अपहरण नहीं होगा, सभी लोग लिखकर दें, उसके बाद हम इस्तिफा देने के लिए तैयार हैं, सारे पार्टी के लोग लिखकर दें । इस्तिफा के बारे में बार-बार क्या कहते रहते हैं । आज ही लिखकर दीजिए, हम भी इस्तिफा देने के लिए तैयार हैं । क्या किसी दूसरे की सरकार रहेगी तो हत्या नहीं होगी ?

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : श्री लालू प्रसाद जी से पूछ लीजिए, नहीं तो हमलोग लिखकर देने के लिए तैयार हैं ।

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : माननीय मुख्य मंत्री जी, आप जरा बैठिए । मैं यह कहना चाहता हूं....

टर्न-28/आजाद/13.7.2000

श्री भोला प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था पर हूं, श्रीमती राबड़ी देवी सदन के नेता हैं और श्री लालू प्रसाद जी इस सदन के माननीय सदस्य हैं । सदन के नेता के आदेश से कोई भी माननीय सदस्य, जो उस दल के माननीय सदस्य हैं, वे बैठ सकते हैं । किसी भी माननीय सदस्य को बैठाने का अधिकार है सदन के नेता को । इसलिए सभापति महोदय, हम/ श्री लालू जी से कहना चाहते हैं कि श्रीमती राबड़ी देवी जी सदन के नेता हैं, वे घर में आपकी धर्म पत्नी हो सकती है ।

श्री लालू प्रसाद : माननीय श्री भोला बाबू, मैं आपको आश्वस्त करता हूं और स्मारित करता हूं कि माननीया श्रीमती राबड़ी देवी सदन के नेता हैं । लेकिन जब दो आदमी के बीच में वार्त्तालाप हो रहा हो, माननीय श्री नन्दकिशोर यादव जी और मुख्य मंत्री के बीच में तो बीच में तीसरा आदमी, नेता, विरोधी दल को नहीं बोलना चाहिए । मैं भोला बाबू से कहना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री सदन के नेता हैं और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहां हमारी सरकार है । पार्टी बड़ी होती है, सरकार बड़ी नहीं होती है । इसलिए श्री भोला बाबू को हम एक सुझाव देना चाहेंगे कि हम आपको बड़ा भाई मानते हैं, आप हमलोगों के डिस्कसन में पार्टी मेट न करें ।

टर्न-29/13.7.2000

हसनैन क्रमशः

श्री नन्द किशोर यादव: सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुये कहना चाहता हूं कि मैं मना करता हूं अपने नेता को राबड़ी देवी की सरकार से नैतकिता के आधार पर इस्तफा मांगने को क्योंकि सरकार नैतिकता नहीं जानती है। मैं केवल सरकार को प्रताड़ित और सरकार की आलोचना करने के लिये यह बात नहीं कह रहा हूं, मैं सरकार को उसका चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सुशील कुमार जी से कहता हूं कि आप इस्तफा मत मांगिये। सुशील कुमार जी से कहता हूं कि थोड़ा सद्गुण सरकार के मन में आजाय ताकि वह चुल्लू भर पानी में डूब कर खुद मर जाय। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शाहिद अली खां: सभापति महोदय, मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी वाद विवाद चल रहा है। सब से पहले मैं भाइ नन्द किशोर यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कहा कि विरोधी दल के नेता भी सरकार के विरोध में बोलते हैं तो मैं उनसे लड़ाई लड़ता हूं कि सरकार अच्छा काम कर रही है इसलिये सरकार को इस्तफा देने और सरकार के विरोध में बोलने का काम मत कीजिये। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, सरकार ने पिछले दस सालों में जो काम किया है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार की जो आज की स्थिति है वैसी पहले नहीं थी। आज की स्थिति और पहले की स्थिति में तुलना किया जा सकता है। जितनी चुस्त दुरूस्त सरकार राष्ट्रीय जनता दल की है, श्री लालू प्रसाद और श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार है वह भी किसी से छुपी हुई नहीं है। सचिवालय समन्वय सेवा में वर्ष 97-98 में 56 करोड़ 49 लाख 49 हजार रूपया खर्च हुआ था उसकी तुलना में 2000-02 में 64 करोड़ 63 लाख

टर्न-29/13.7.2000

हसनैन

43 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है । यह प्रावधान इसलिये किया गया है कि यहाँ के कर्मियों को केन्द्रीय वेतनमान दिया जा रहा है । केन्द्रीय वेतनमान के चलते यह बढ़ोत्तरी हुई है । सरकार ने वर्ष 98-99 में 75 करोड़ 92 लाख 44 हजार रूपये खर्च किया वहीं सरकार को केन्द्रीय वेतनमान के चलते 1 अरब 2 करोड़ 31 लाख 30 हजार रूपये का प्रावधान करना पड़ा है । जिला प्रशासन के योजना मद में 99-2000 में 57 करोड़ 40 लाख था जबकि इस वित्तीय वर्ष 2000-2001 में 43 करोड़ 51 लाख 70 हजार रूपय खर्च करने का प्रावधान है । क्रमशः

टर्न-30/ अशोक
13-7-2000

श्री शाहिद अली खाँ : क्रमशः सभापति महोदय, बिना जिला को चुस्त-दुरुस्त रहे, बिना इसके बिहार का प्रशासन नहीं चल सकता है, आज गवाह है, बिहार में पहले जो धार्मिक उन्माद फैला हुआ था, आज बिहार का जिला प्रशासन चुस्त-दुरुस्त होने के कारण बिहार में एक भी जगह कहीं पर विवाद नहीं उठता है और धर्मनिरपेक्ष सरकार अच्छी तरह अपनी सरकार चला रही है। माननीय श्री लालू प्रसाद एवं श्री मती राबड़ी देवी ने आम जनता के सामने जो वायदा किया उसको वे पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार अच्छे एवं सक्षम पदाधिकारी को विकास कार्य में लगा रही है और विकास के कार्य प्रगति के रास्ते पर बढ़ती जा रही है और जहां भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध निगरानी विभाग के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है, उनको दण्डित करने का काम भी सरकार कर रही है, इससे साफ जाहिर है कि हम अच्छा प्रशासन देने के लिये तत्पर हैं, हम चाहते हैं कि हम अच्छा सरकार दे सकें।

सभापति महोदय, बिहार में इन 10 वर्षों में जिलों का निर्माण, अनुमण्डल का निर्माण, प्रखण्ड का निर्माण हुये हैं, इस निर्माण के चलते आम जनता को सहूलियत हुई है। जो गरीब-गुरुबा गांव में रहते हैं, जिन्होंने कभी जिला, अनुमण्डल और प्रखण्ड देखा नहीं था आज वे प्रखण्ड में जाते हैं और प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से अपनी समस्याओं को बोलते हैं। प्रखण्ड बढ़ने से, अनुमण्डल बढ़ने से, जिला के निर्माण करने से विकास के कार्य हुये हैं, आम गरीब लोग जो हैं उनका उत्थान हुआ है और गरीबों का मनोबल बढ़ा है। इसी के तहत मैं भी चाहता हूँ, मैं माननीया मुख्यमंत्री से आग्रह करुंगा कि सीतामढ़ी जिला में बाजपट्टी प्रखण्ड है उसके अन्तर्गत जो बड़हरवा है उसको प्रखण्ड बनाया जाय ताकि आम जनता को सहूलियत मिल सके और उस इलाके का विकास हो सके। बड़हरवा को प्रखण्ड जो बनाया जाय उसमें सात पंचायत- हरपुरवा, बड़हरवा, मुरौल, मदारीपुर, रतवारा, सौरा एवं हिमायुपुर को मिलाकर बनाया जाय। बड़हरवा प्रखण्ड का निर्माण किया जाय- इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

टर्न-३०/ अशोक
१३-७-२०००

श्री मो० अब्दुल्लाह : माननीय सभापति महोदय, मंत्रिमंडल सचिवालय के कटौती-प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ- कटौती-प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मंत्रि मंडल जो आपकी सरकार का बना है इससे आंक सकते हैं आप कि इस सरकार में विधायक कम है और मंत्री ज्यादा है। इतना बड़ा मंत्रिमंडल बनाने के पीछे मंशा यह है कि राजनीति स्थिरता बनी रही, मंत्रियों पर इतना खर्च हो रहा है, सरकार की मंशा नहीं है कि ये पैसे गरीबों तक जाय। मंत्रिमंडल पर जो सरकार व्यय कर रही है, वर्ष १९९९-२००० में ९ करोड़ ५९लाख३०हजार और इस साल का बजट है, वर्ष २०००-२००१ का बजट है ११ करोड़ ४४ लाख ४६ हजार। सरकार पर जो व्यय बढ़ रहा है, मंत्रिमंडल पर जो खर्च हो रहा है उस पैसे पर गरीबों का हक है, लेकिन सरकार इन पैसों को गरीबों पर खर्च नहीं कर रही है। सरकार के पास योजना मद में पैसा नहीं है, और गैर-योजना मद में पैसा खर्च किये जा रही है। सभापति महोदय, राज्य सरकार जो भी प्रतिवेदन अभी बांट रही है, उसमें कहीं भी, किसी भी पन्ने में अंकित नहीं है कि सरकार की क्या उपलब्धि है, उपलब्धि का जिक्र नहीं है, सरकार की इस चार महीने की क्या उपलब्धि है और वर्ष २०००-२००१ में क्या उपलब्धि प्राप्त करने जा रही है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्रमशः

क्रमशः

श्री मो० ओवैदुल्लाह : सभापति महोदय, अगर सरकार पंचायतों का चुनाव करा लेती तो आज जो सेंटर के पैसे 5 करोड़ रुपये हैं वह नहीं रुकता । सरकार अपने पैसों को खर्च नहीं कर पाती है । व्योरा बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भेजती इसलिए सेंटर से पैसा नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से यह सरकार केन्द्रीय अनुदान से वंचित है । सभापति महोदय, केवल पंचायत का ही उदाहरण नहीं है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे कई एक मद में रुक गए हैं जिसकी वजह से जो गरीबों का घर बनना चाहिए वह काम रुक गया है, लाल कार्ड की योजना रुक गयी है । आज गरीबों का घर इन्दिरा आवास में नहीं बन रहा है बल्कि पक्का वाले लोगों का घर बन रहा है । इस बात को पूरा सदन जानता है । घर बनाने में किसतरह के घपले हो रहे हैं इसको सब कोई जानताहै । सरकार इसतरह के घपले को रोक पाने में अक्षम है । ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है । पिछले 10 वर्षों में यह सरकार किसी गांव में बिजली नहीं लगा सकी है । इस सरकार से क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि वह सरकार बिजली भी नहीं लगा सकती है । सभापति महोदय, इनका जो मंत्रिमंडल है उसके सदस्यों में आपस में मेल नहीं है । कैबिनेट मंत्री कुछ कहते हैं, स्टेट मिनिस्टर कुछ कहते हैं । इसका उदाहरण है, जो एक मंत्री जी का बयान है उसको मैं पेश कर रहा हूँ । जंगल काटने वाले को वन मंत्री बनाया गयाहै । यह जो बागुन सुम्ब्रुई जी का स्टेटमेंट है । इसको आपलोगों ने पढ़ा होगा । यह स्थिति है इनके मिनिस्टरों में आपस में मेल नहीं है । केवल सरकार फौर्मलटीज निभा रही है ।

श्री विश्वमोहन शर्मा (मंत्री) : सभापति महोदय, बागुन सुम्ब्रुई जी ने इसको डिनाई कियाहै, उनका कहना है कि यह मेरा स्टेटमेंट नहीं है लेकिन ये उसका हवाल दे रहे है इसलिए इसको कार्यवाही से हटवा दिया जाय ।

श्री मो० ओवैदुल्ला : सभापति महोदय, सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि पिछले दस वर्षों में कितने गांवों में बिजली लगी है । सरकार पहले ही एनाउन्स कर चुकी है

टर्न-31/ज्योति/13-7-2000

500 कुछ गांवों को बिजली दी गयी है । वहां बिजली नहीं दी गयी है बल्कि खम्भे गाड़े गए हैं और उस खम्भे में आज गाय,बैल और भैंस बांधे जा रहे हैं , किसी में तार नहीं है,तार है तो ट्रांसफौर्मर नहीं है , ट्रांसफौर्मर है तो बिजली नहीं है और यदि बिजली आती है तो बच्चे के पढ़ने के समय में नहीं आती है ,रात में सोने के समय में आती है । यह सरकार इतनी अक्षम है कि वह केवल पैसे का बंदरबांट करने की छूट लोगों को दे रखी है । गरीबों के हित में किसी योजना को चालू नहीं करा सकती, गरीबों को बिजली नहीं दे सकती । सच्ची बात बतलाऊं कि यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है । सरकारी बेंच की तरफ से अब्दुल गफूर साहेब बयान दे रहे थे कि कलाम पाक का ठोंगा बनाकर बेंचा जा रहा था और इसके लिए जब घटना स्थल पर राजद अध्यक्ष जाते हैं तो वहां का माहौल और बिगड़ जाता है और आज ये कहते हैं कि अल्प संख्यक के हितों के लिए यह सरकार है । यह सरकार कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं करा रही है । आज दंगा बंद क्यों हो गया चूंकि जो दंगाई थे वे सब इधर आ गए हैं इसलिए आज दंगा बंद हो गया है । सच्चाई यही है । आज मदरसा के टीचर भूखे मर रहे हैं । उनको वेतन नहीं मिल रहा है । आज यह कहती है कि अल्पसंख्यकों के हित की सरकार है लेकिन आज जो चपरासी को वेतन मिलता है वह भी मदरसा के शिक्षकों को नहीं मिल रहा है ,उस्ताद को नहीं मिल रहा है । मुट्ठी भर अमीरों की यह सरकार है और उन्हीं के लिए यह कटिबद्ध है । यह गरीबों की कतई सरकार नहीं है,अल्पसंख्यकों की कतई सरकार नहीं है । यदि अल्पसंख्यकों की सरकार रहती तो कलाम पाक को ठोंगा बनवाकर नहीं बेचवाती और उसमें बाजार का सामान नहीं बेचा जाता । अल्पसंख्यक मर जाना कबूल करेंगे लेकिन इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ।

क्रमशः

टर्न-32/पंचजय /13-7-2000

क्रमशः

श्री मो0 ओबैदुल्ला : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि लोक सेवा आयोग ने 287 सफल उम्मीदवारों को महिला एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु चयनित किया । पिछले वर्ष 22-7-99 को इनका चयन हुआ था और आगामी 22-7-2000 को पैनल से नियुक्ति होने की अवधि समाप्त हो जायेगी और अबतक सरकार इन उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र अबतक निर्गत नहीं कर सकी है । यदि अवधि 1 साल की समाप्त हो जायेगी तो फिर से सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और फिर से पैसा खर्च करना होगा । ये सारे पैसे गरीबों के पैसे हैं और आप बेरहमी से गरीबों के पैसे खर्च कर रहे हैं । आज 287 उम्मीदवार जो चयनित हैं ये बहाल हो गए रहते तो बच्चे एवं महिलाओं के विकास कार्यों में जहाँ महिलाएं जुटतीं वहीं दूसरी तरफ उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती और सरकार की भी उपलब्धि हासिल होती ।

सभापति महोदय, आज ब्लौक स्तर पर लूट मची हुई है । ग्राम सेवक से लेकर बी0डी0ओ0 तक सब इसमें शामिल हैं । ये तमाम लोग ब्लौक को लूट का मशीनरी बनाकर रखे हुए हैं । पंचायत का चुनाव हो गया रहता तो मुखिया प्रभार में रहते और विकास का कार्य ठीक कराते लेकिन बी0डी0ओ0 लोगों को आज खुलेआम लूट करने की छूट मिली हुई है । ग्राम सेवक हों या बी0डी0ओ0 हों तमाम लोग रिश्वत ले रहे हैं

(व्यवधान)

बी0डी0ओ0 की पीटाई मैंने की है, वह इसलिए की है कि वह घूस नहीं ले, मैं स्वीकार करता हूँ कि यह सही बात है । सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं । आज सभी प्रखण्ड में बी0डी0ओ0 रिश्वत लेते हैं । रिश्वत की बात सरकार की जानकारी में है । ग्राम सेवक आज गरीब लोगों का लिस्ट नहीं बनाते हैं, गरीबों को छोड़कर जो पैसे वाले लोग हैं, पक्का मकान में रहने वाले लोग हैं, मोटर सायकिल रखने वाले लोग हैं, मेरे प्रखण्ड का भी उदाहरण है, जिनका पक्का का मकान बना हुआ है

... उनका इन्दिरा आवास के लिए लिस्ट में नाम रखेंगे लेकिन जो गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं उनका नाम उस लिस्ट में नहीं शामिल करेंगे। सभापति महोदय, इसलिए यह अक्षम सरकार है और इस अक्षम सरकार को अपना ... मंत्रिमंडल का आकार छोटा करना चाहिए। जनहित में गरीबों के हित में इस सरकार को काम करना चाहिए।

सभापति (श्री गणेश प्रसाद यादव): माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्य श्री इन्दर सिंह नामधारी जी, अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री इंदर सिंह नामधारी : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया ।

सभापतिजी, मंत्रिमंडल सचिवालय और समन्वय ऐसा विषय है जो सारे प्रशासन की कुंजी है । यह डेमोक्रैटिक सेट अप है सभापति महोदय और सारी शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित रहती हैं । मैं चाहता था कि हमारे लालू प्रसादजी सदन में होते तो मुझे बोलने में आसानी होती क्योंकि आज बिहार में डी-फैक्टो चीफ मिनिस्टर वही हैं, राबड़ी देवीजी डी-जीरो चीफ मिनिस्टर हैं । लैटिन में दो तरह के शब्द हैं डी-फैक्टो और डी-जीरो ।

डा० रामचंद्र पूर्वे (मंत्री) : सभापति महोदय, राबड़ी देवजी बिहार की मुख्यमंत्री हैं, सम्पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री हैं ।

श्री इंदर सिंह नामधारी : पूर्वेजी, मैं यह कह रहा था कि डी-जीरो मुख्यमंत्री हैं और लालू प्रसादजी डी-फैक्टो मुख्यमंत्री हैं ।

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, राबड़ी देवीजी, आप बैठ तो जाइये नामधारीजी ।

श्री इंदर सिंह नामधारी : सभापति महोदय, हमको लालूजी कहते हैं कि आप बैठ जाइये । सभाध्यक्ष भी आप ही हैं डी-फैक्टो ।

श्री लालू प्रसाद : आपने आरोप लगा दिया, इसलिये ~~हमको~~ हमारा हक बन जाता है डिफेंड करने का । यह हमारा राईट है, इसको छीना नहीं जा सकता है ।

महोदय, राबड़ी ~~देवी~~ देवीजी को माननीय सदस्यों ने नेता चुना, यह निर्विवाद बात है । राबड़ी देवीजी स्वयं बिहार की मुख्यमंत्री हैं । राबड़ी देवी का सरकार पर नियंत्रण और संचालन है । राबड़ी देवीजी, हमारी पार्टी की सरकार है, हम उसके अध्यक्ष हैं, उसकी पार्टी की चीफ मिनिस्टर हैं । लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं नामधारीजी कि आपकी स्थिति आपकी पत्नी के समक्ष क्या है, इसे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है । हम तो राबड़ी देवी से लड़ते रहते हैं लेकिन आपको हिम्मत नहीं है अपनी पत्नी से लड़ने की ।

~~श्री~~ श्री इंदर सिंह नामधारी : सभापति महोदय, मैंने यह बातें इसलिये कही थीं कि मैं यह कहना चाहता था कि -

"कहनी है मुझको अजब इक कहानी,
न ऐसी नयी है, न ऐसी पुरानी,
न समझो तो गैरों का है ये फसाना,
जो दिल से सुनो तो ये अपनी कहानी ।"

सभापतिजी, मैं मंत्रिमंडल की आलोचना करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हुआ हूँ । "कहनी है मुझको अजब इक कहानी, न ऐसी नयी है, न ऐसी पुरानी" जो आज मंत्री बैठे हैं, वहां, कभी हम भी इनकी बगल में बैठते थे, कोई ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है । मैं कुछ बातें इसलिये रखना चाहता हूँ कि इस मंत्रिमंडल, जिसको मैंने कहा कि यह प्रशासन की कुंजी है, इससे बिहार की दस करोड़ जनता को लाभ हो, मंत्रिमंडल सचिवालय को इतना पैसा दिया जा रहा है तो बिहार की जनता लाभान्वित तो हो । मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिये कहा था कि लालूजी सदन में होते तो आसानी होती, मैं धन्यवाद उनको ज्ञापित करता हूँ, इसलिये ~~अ~~ कि मैं उदाहरण देना चाहता हूँ प्लेटो का ।

सभापति महोदय, जिसने सबसे पहले प्रजातंत्र की परिभाषा दी थी, उसने कहा था -"सरकार और ब्यूरोक्रैसी में रिश्ता होता है कुत्ते और पूँछ का।" महोदय, कुत्ते का जो शरीर होता है वह है मंत्रिमंडल और पूँछ जो है वह ब्यूरोक्रैसी है । जब कुत्ते का शरीर हिले तो पूँछ को हिलना चाहिये । आज मंत्रिमंडल जीरो हो गया है, ब्यूरोक्रैसी हावी हो गयी है । अगर मैं यह बात कहता हूँ तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिये और मंत्रियों को अपने गिरेबां में झांक कर देखना चाहिये कि क्या शक्तियां हैं उनको । क्या ~~अ~~ सेक्रेटरी के इशारे पर मंत्री नाचते हैं या नहीं ? लालू यादवजी के सिवा किसी की चलती नहीं है । यह एक हीरो हैं, बाकी सब जीरो हैं । एक हीरो होना चाहिये, लेकिन सबको जीरो करना इसके लिये जरूरी नहीं है ।

सभापति महोदय, मैंने इनके साथ रहते हुए विधायक दल की बैठकों में, आप भी उस समय एक साथ थे, कहा करता था, लालूजी, प्रकृति ने आपको समय दिया है । यह मौका बार-बार हाथ में नहीं आता है । आपकी बात कानून है । आप इसका ~~ठ~~ फायदा उठायें । मैंने प्रताप सिंह कैरो का उदाहरण दिया था, मुख्यमंत्री बनने के पहले गांव में गये थे वे, एक गरीब आदमी ने कहा मुझे कुंआं चाहिये, उन्होंने चुनाव के बाद । चुनाव के बाद कैरो मुख्यमंत्री बन गये ।

...क्रमशः...

टर्न-34/राजेश/13.7.2000

श्री इन्दर सिंह नामधारी(क्रमश:):- शपथ लेने के बाद जब वे सेक्रेटेरियट गये तो वहाँ के कलक्टर को उन्होंने फोन किया कि फलाँ गाँव में हम गये थे, 8 दिनों के अंदर कुँवा का उद्घाटन करेंगे, इसलिए काम को शुरू किया जाय । सभापति महोदय, वे मुख्यमंत्री बनने के पहले वादा करते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले काम वहीं शुरु होता है । जो आपने कहा था लालू जी, आपने क्या कहा था। रामनवमी के दिन 29 लोगों की जानें चली गयी, रात को 11 बजे आपने मुझे फोन किया, मेरे पतोहू ने टेलिफोन को रिसिभ किया, उस समय आप बेउर जेल में थे, ढ़ाई बजे रात को आपको सूचना मिली, पौने दो बजे रात की यह घटना है, आप एक सजग मुख्यमंत्री हैं, जेल से आप फोन करते हैं, लेकिन फोन करने के बाद भूल जाते हैं । फिर आपने सबेरे 7 बजे फोन किया और आपने कहा कि जितने लोग मारे गये हैं, उन सभी को एक-एक लाख रुपया और नौकरी दी जायेगी, आप एनाउन्स कर दीजिये । महोदय, आज तीन महीना हो गये, क्या यह आपका फर्ज नहीं था कि आप जो बोलें उसपर अमल करें । इसलिए हमलोगों को लगता है कि आप जो बोलते हैं, उसके प्रति आप कितना गंभीर रहते हैं, कितना गिरफ्त है, आपका प्रशासन पर, आप जरा सोचिये । आपके साथ ऐसा तेज आई0ए0एस0ऑफिसर होना चाहिए कि जो आप बोले, उसको वे नोट करे और जबरदस्ती उसपर आपसे साइन करवा लें । लेकिन आप तो बोलते हैं और फिर ~~उसे~~ भूल जाते हैं ।

श्री लालू प्रसाद:- माननीय सदस्य नामधारी ने आरोप लगाया है, इसलिए हम तो बोलेंगे ही ।

सभापति(श्री गणेश प्रसाद यादव):- आरोप तो नहीं लगाये हैं, आपका तो प्रशंसा किये है।

श्री लालू प्रसाद:- उन्होंने मेरा नाम लिया है, इसलिए हमको बोलने दिया जाय । महोदय, गरीब लोग मरे थे, प्राकृतिक आपदा से, बिजली से, आपके सामने सभी लोगों को ~~सेंसर~~ करके, सारे लोगों को एक-एक लाख रुपया डी0सी0पलामू के पास सारा पैसा सैंक्सन करके चला गया । आपके साथ तय भी हुआ था, मुख्यमंत्री जी जब रहेंगी तो वह देंगी, यह बोला गया था महोदय । लेकिन महोदय, मैं चावला जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने सूचना दी कि लोटो में भी 12 लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के मारे गये थे, उनको भी घोषणा थी, अगर आज इनको देते हैं और उनको दूसरी बार देंगे तो उनके मन में दूसरी बात आयेंगी, दोनों का पैसा एक साथ सैंक्सन करके एसेम्बली के बाद तय होगा, चलकर लोटो वाले लोगों को और दूसरे जो मारे गये हैं, दोनों को दे दिया जायेगा । आपने तो इस तथ्य को छिपा लिया और दूसरी बात आप बोल रहे हैं ।

श्री इन्दर सिंह नामधारी:- महोदय, आप देखे हैं, लालू जी डंडी मारना कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं सभापति महोदय, मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि आपने मुझसे कहा कि एक लाख रुपया और आश्रितों को नौकरी। सभापति महोदय, ऐसे-ऐसे जवान लड़के मरे हैं, जिनकी पत्नियों के हाथ को मेंहदी नहीं सूखी है, आप नौकरी को क्यों भूलते हैं, जो आपने आदेश दिया है, वह केवल एक लाख रुपये का है, नौकरी का कहीं भी जिक्र नहीं है। यह क्या। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रताप सिंह कैरो एक जिला के बारे में सोचता था, लेकिन आप तो जिला को जिला भूल जाते हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि लालू जी केवल बात आपकी चलती है, यह केवल सिद्ध करता है कि आप कितने सिरियस हैं, बिहार की जनता की समस्याओं के प्रति। सभापति महोदय, लातेहार जिला, आज से 6 साल पहले, मैं गवाह हूँ, यह तय हुआ था कि लातेहार को जिला बनायेंगे क्योंकि पलामू को प्रमंडल बना दिया गया है, गढ़वा को जिला बना दिया गया है तो लातेहार को भी जिला बनायेंगे। महोदय, हैलीपैड भी बन गया, जिस दिन उद्घाटन करना था, ठीक 9 बजे मेरे पास फोन लालू जी का आया कि पत्नी की तबियत खराब हो गयी है, लालू जी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, पत्नी की तबियत खराब होने के कारण हमलोग दिल्ली जा रहे हैं, दो दिन के बाद इसका उद्घाटन करा दीजियेगा। एक तरफ इनकी पत्नी की तबियत खराब है, इनकी पत्नी का इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना है, तो मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि पत्नी की तबियत खराब रहने के बावजूद आपको लातेहार जिला का उद्घाटन करने के लिए कहूँ। इसलिए मैंने लालू जी से कहा कि आप दिल्ली से इलाज कराकर पत्नी का आइये और लालू जी ने मुझसे कहा कि दूसरे दिन दिल्ली से इलाज कराकर चला आऊँगा और लातेहार जिला का उद्घाटन करूँगा।

क्रमशः

श्री इन्दर सिंह नामधारी (क्रमश:) मुख्यमंत्री बने तीन साल हो गये । अभी तक लातेहार जिला नहीं बना । हेलीपैड टूट गया । हाई कोर्ट के आदेश की बात करते हैं, उसके बाद भी जिला बना। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि लातेहार को जिला बना ही दीजिए । हाउ मच यू सिरियस। बिहार की समस्याओं के लिए आप कितना गंभीर हैं? इतना ही नहीं, एक तरफ आपने ऐतिहासिक काम किया। आपने पलामू को प्रमंडल बनाया । एक लाख जनता की भीड़ के सामने पलामू जिला स्कूल के मैदान में प्रमंडल की घोषणा की जा रही थी तो हमने लालू जी को कान में कहा कि यहाँ स्टेडियम एक बनना चाहिए इसकी भी घोषणा आज कर दें। आपने कहा सुझाव तो बहुत अच्छा है। भाषण देने में क्या खर्च है? आप खड़े होकर तुरंत स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी। मैं आज आठ वर्ष बाद पूछ रहा हूँ कि क्या आपने स्टेडियम को बनवाया? एक मुख्यमंत्री की घोषणा थी एक लाख जनता के सामने। आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने अपने विधायक कोटा का सारा पैसा खर्च कर दिया स्टेडियम बनाने के लिए और स्टेडियम बना दिया । सभापति महोदय, पैसा सरकार का ही है । जब सरकार खुद बोल रही थी कि यहाँ पर स्टेडियम बनेगा । हम पटना आये और लालू जी से मिले। इन्होंने मुकुन्द जी को बुलाया और कहा कि 3 लाख रूपया पलामू भेज दीजिए ।लेकिन सभापति महोदय, 3 लाख रूपये के बदले 3 रूपया भी वहाँ नहीं गया । मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ । मैं एक बात कह रहा हूँ लालू जी, समय बार-बार नहीं आता है, कुर्सियाँ बदलती है, बड़े-बड़े शहनशाह की शक्ति बदलती है फिर खाली हाथ बच जाते हैं केवल उनके कारनामें ही रह जाती है। सभापति महोदय, जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है, मंत्रिमंडल की इज्जत लालू जी आपकी इज्जत है। अगर मंत्री जलील होते हैं तो आप समझिये कि आप भी जलील होते हैं लेकिन, आज जब सेक्रेटरी-मंत्री लड़ता है तो आप लालू जी इन्ज्वाय करते हैं। रमई राम जी आप क्यों बोल रहे हैं? आपकी कितनी चलती है मैं जानता हूँ। यह कोई हंसी की बात नहीं है। मैं जब-जब बोलता हूँ लालू जी आप गवाह हैं मैंने आपको सुझाव ही दिया है, अच्छा सुझाव दिया है, आपको जलील करने के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ वास्तव में सारी शक्ति आपके हाथ में है। मैंने डी0 जीरो और डी0 फक्टो की बात की । आप एक घंटा बोलने की बात कहकर क्या हमको डराना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कभी आपने मंत्री को बुलाकर उनके विभाग के कार्यों की समीक्षा की? मैं आपके साथ ढाई वर्ष तक मंत्री रहा मेरी तमन्ना थी कभी मुख्यमंत्री मुझे बुलाकर जानकारी लें कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन मैंने काम किया? कितनी जमीन

आपने बाँटी? अच्छा काम अगर होगा तो नाम आपका ही होगा । लेकिन आपको कभी टाईम नहीं मिला किसी मंत्री के विभाग की समीक्षा करने के लिए। आपने 5-6 वर्ष पहले प्रोग्राम बनाया था प्रमंडलीय मुख्यालय में समीक्षा करने के लिए। आप राँची जाईए । अभी इन्दिरा आवास की बात श्री नन्दकिशोर जी बोल रहे थे । इन्दिरा आवास, सुनिश्चित रोजगार योजना में क्या घपला हो रहा है? कल हजारीबाग के डी0डी0सी0 के निलंबन की घोषणा आपने इशारा देकर करवाई। आप बैठिए और अफसरों से पूछिए . डी0डी0सी0/डी0सी0 से पूछिये कि कितना पैसा दिया? कितना आपने खर्च किया? 2-4 योजनाओं का निरीक्षण भी कीजिए इससे बहुत सारी शिकायतें हद तक दूर हो जायेगी । लेकिन आपको तो पोलिटिकल तिकड़म से ही फुर्सत नहीं मिलती है।

(क्रमशः)

श्री इन्दर सिंह नामधारी (क्रमशः): मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कभी समीक्षा की कि कितनी संचिका लंबित हैं बिहार में, किसे अनुकंपा पर बहाली चाहिए, कितने लीज के मामले हैं । मेरी जानकारी में 40-50 हजार फाईलें लंबित पड़ी हुई हैं ।

श्री रामचन्द्र पूर्वे (मंत्री): ऐसी बात नहीं है । यह गलत है ।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: महोदय, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मैं कहता हूँ कि आप भेरीफाई कर लीजिए । मेरी जानकारी है कि 40 हजार फाईल लंबित हैं ।

श्री रामचन्द्र पूर्वे (मंत्री): यह बिल्कुल गलत बात है । सरकार के स्तर पर कोई संचिका लंबित नहीं रही है ।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: अगर उन संचिकाओं पर साईन हो जाये, जो पौलिटीकल पैरवी करनेवाले लोग हैं, अगर उन संचिकाओं पर साईन हो जायें जिनकी अनुकंपा के आधार पर बहाली होनी चाहिए, आपके स्तर से फाईनल डिसपोजल तो/हो जाये चूंकि आप डेमोक्रेटिक सेट-अप का मुखिया हैं । आपके साईन के बाद ही कोई ऑर्डर होना है ! आप देखिये कि बिहार की किस्मत कैसे बदला जाये । जगदाबाबू कह रहे थे कि बिहार को जान-बुझकर बदनाम किया जा रहा है । मैं इस विचार का हूँ कि बिहार को बदनाम नहीं करना चाहिए । बिहार की जो छवि दूसरी जगह जाती है, उसके लिए मुझे भी चिंता है । एक कहावत है :-

" डूबेगी कस्ती, डूबेंगे सारे,
न हम ही बचेंगे, न बचेंगे सारे ।

इसलिए उस नाव को बचाना मेरा भी काम है । मैं मंत्रि मंडल के बारे में कहना चाहता हूँ कि मंत्रिमंडल की संख्या मजबूरी में बढ़ी है । आप खुशी से मंत्री बनाइये । कुछ मजबूरियां हो सकती हैं । मैं कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूँ जिसमें सारे के सारे दुल्हा हैं और एक भी बाराती नहीं हैं । एक माननीय सदस्य श्री अब्दुल जलील मस्तान जब भाषण दे रहे थे तो मैंने माननीय मंत्री श्री फुरकान अंसारी से पूछा कि ये दुल्हे कैसे बच गये । उन्होंने कहा कि ये अंदर की बात है । माननीय मंत्री श्री फुरकान अंसारी यहां होते तो वे बताते । ज्यादा मंत्री बनाना आपके लिए मजबूरियां थीं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इससे भी बड़ा जेम्बो-जेट मंत्रिमंडल बना, दिल्ली में भी बना । कुछ पौलिटीकल मजबूरियां होती हैं । शीशे के घर में रहनेवाले को दूसरे के घर में पत्थर फेंकने का कोई अधिकार नहीं होता है ।

टर्न-35/13.7.2000

सिन्हा ।

(90)

सभापति (श्री गणेश प्रसाद यादव): माननीय सदस्य, आप अपना भाषण एक मिनट में कनक्लूड करें ।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: महोदय, मैं आपके आदेश से ही बोल रहा हूँ ।

श्री लालू प्रसाद: जब आपके साथ थे तो 75 की संख्या थी और अभी उससे पांच ज्यादा है ।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: लालू जी, आप हिन्दुस्तान में अनपैरेरल हैं । राजनीतिक तिकड़मबाजी में आपका कोई जवाब नहीं है । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपने मंत्रिमंडल बनाया, यह आपकी मजबूरी थी लेकिन वह ठीक-ठाक रहे, कम-से-कम मंत्रियों की डिगनिटी रहे । आप बताइये कितने ठीक चल रहे हैं? आप जनता के बीच जाइये और इन मंत्रियों के बारे में जनता क्या कहती है, जनता का क्या ओपीनियन है, इसको पता कीजिये ।

हमारे डाल्टेनगंज में एक मेदनी राजा थे । वे रात में भेस बदलकर घुमते थे यह जानने के लिए कि जनता उनके बारे में क्या कहती है । साईरन बजती हुई गाड़ी पर बैठकर घुमना अलग बात है । आप अकेले जाइये लोगों के बीच में, वहां आप बैठिये और यह जानने की कोशिश कीजिये कि सरकार के बारे में लोग क्या सोचते हैं? माननीय सदस्य श्री सुरेश पासवान के कहने पर सरकार नहीं चलेगी ।

(क्रमशः)

श्री इन्दर सिंह नामधारी (क्रमश:)- खासकर पासवान लोग आपकी प्रशंसा में ज्यादा गीत गा रहे हैं। लगता है कि श्री राम विलास पासवान जी मुआवजा दे रहे हैं। आपने गीत गाना शुरू किया, गायें, लेकिन आम जनता क्या सोचती है यह देखें ।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा । मैं पलामू जिला की बात बताना चाहता हूँ। पिछले बीस सूत्री की बैठक में पता चला कि साढ़े पांच करोड़ रुपये पिछले पांच सालों से कल्याण विभाग का अनयूज्ड पड़ा हुआ है । केवल पलामू जिला में ही नहीं, बल्कि हरेक जिला में 5 करोड़ रुपये, 6 करोड़ रुपये , 7 करोड़ रुपये पड़े हुये हैं। कुल 55 जिले हैं , जोड़कर आप देख लीजिये, कितना रुपया हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मंत्रिमंडल सक्षम हो जाये तो यह स्थिति नहीं रहेगी । लेकिन ये पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। कहते हैं कि हमलोग दिशा-निर्देश मांग रहे हैं । कैसे हैं आपके पदाधिकारी जो सालों से कोई दिशा-निर्देश नहीं देते हैं। कोई कुछ दिशा-निर्देश दे रहा है तो कोई कुछ दिशा-निर्देश दे रहा है । कहीं कोई समन्वयन नहीं है। आज सदन में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय, निर्वाचन, नागरिक, विमानन, संसदीय कार्य, विधान-मंडल तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग पर सरकार की ओर से मांग प्रस्तुत किया गया है । लेकिन कोई समन्वयन नहीं है। तो पैसा किसलिये दिया जाये । मैं कहना चाहता हूं कि आप समन्वयन रखिये और मंत्रिमंडल को सक्षम रखिये । मैं कहता हूं कि मंत्रियों की डिगनिटी होती है। एक जमाना था आप स्टैंड लिये थे। मैं आपसे सीनियर [illegible]

[illegible]

हूं। श्री रामदेव महतो पटना सिटी के थे । वे सहकारिता मंत्री बने । एक बार श्री ए0के0एम0हुसैन ने मुझसे कहा कि मंत्री जी से बात करने के लिए पांच मिनट का समय ले लीजिये । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एक सीनियर आई0ए0एस0

मंत्रियों से समय मांगता था और आज आपके मंत्रियों ने क्या हालत कर दी है ? मंत्री सर्किट हाउस में बैठे हैं और कहते हैं कि कलक्टर को फोन लगाओ और उधर से कहा जाता है कि कलक्टर बाथरूम में हैं। कलक्टर लोग बाथरूम में 24-25 घंटे रहते हैं। आपके मंत्रियों ने आज क्या कर दिया है ? आप लाल-बत्ती लगाकर घूमते हैं। अगर आप जमीन के मंत्री होते, मैं फिरकत रहा हूं, आप कहेंगे कि मंत्रियों को भड़का रहे हैं। लेकिन मैं भड़का नहीं रहा हूं। आज क्या स्थिति है ? अगर हवाई जहाज से उतरते हैं तो एक दारोगा तक वहां रीसीभ करने नहीं आता है। मंत्री घूम रहे हैं, कोई पूछनेवाला नहीं है। हां, आप जब जाते हैं तो एस0पी0 डी0आई0जी0 सलामी देते हैं। आपने मंत्रिमंडल को क्या कर दिया है। ऐसा क्यों होता है ? लट्टू चलती है तो गूंज पर चलती है। लट्टू का बड़ा हिस्सा उल्टा होना चाहिए। अभी केवल गूंज की इज्जत है। इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप हर मंत्री को इज्जत दीजिये। मंत्री अपने विभाग को नीति देता है, सिद्धांत देता है। आप मंत्री को पावर दीजिये। आप केन्द्र से शिक्षा ले सकते हैं। आज बाजपेयी जी प्रधानमंत्री हैं। दूर-संचार मंत्री श्री राम विलास पासवान जी हैं और शरद यादव उड्डयन मंत्री हैं। सभी मंत्री काम कर रहे हैं। सब को आप काम करने का मौका दीजिये। एक हीरो बन गया, बाकी सब जीरो बन गये। क्या यही आप पसन्द करते हैं ? मैं कहता हूं कि आप भी हीरो बनिये और उन्हें भी हीरो बनने दीजिये। उन्हें पावर दीजिये।

महोदय, तड़क-तड़क कर माननीय मंत्री श्री रमई राम जी खड़े हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इनको आप झांसा देते रहेंगे और ये कभी भी उपमुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मैं इनको श्राप दे रहा हूं कि ये कभी भी उप-मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।

सभापति (श्री गणेश प्रसाद यादव)- माननीय सदस्य आप समाप्त कीजिये।

श्री इन्दर सिंह नामधारी :- मैं कन्क्लुड कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से लालू जी को कहना चाहता हूं कि इतिहास ने आपको जो समय दिया है, जो वक्त दिया है

श्री लालू प्रसाद - महोदय, देखिये, रमई राम जी को ये श्राप दे रहे हैं।

श्री इन्दर सिंह नामधारी - मैं अपना श्राप वापस ले लेता हूं।

टर्न-37/ललन
13•7•2000

(93)

श्री इंदर सिंह नामधारी (क्रमश:): मैं अपना आरोप वापस ले लेता हूँ। आपने घोषणा किया था कि रमई राम जी को उप मुख्यमंत्री बना देंगे। आप रमई राम जी को उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपने वचन का पालन किया है। आप कीजिए। आप नहीं करेंगे केवल उनकी आँखों में धूल झोंकेंगे और वे भी ऐसे आदमी हैं कि धूल झोंकाते रहेंगे। उनको अकल नहीं आयेगी। सभापति महोदय, मैं एक लाईन से अपनी बात समाप्त कर दूँगा। सब कुछ वक्त है। लालू जी वक्त जा रहा है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक संकल्प लीजिए। आज मंत्रिमंडल पर विचार हो रहा है। यह सब अमला, काफिला आपका है। आप एक संकल्प लीजिए कि मैं रेव्यू करूंगा, हर मंत्रियों के मंत्रालय का रेव्यू करूंगा। आगे से मंत्री भी अफसरों से कहेंगे कि हम रेव्यू करेंगे।

" आदमी को चाहिए, वक्त से डरकर रहे।
कौन जाने वक्त का, कब बदल जाए मिजाज।
वक्त के दिन और रात
वक्त के कल और आज
वक्त की हर शै गुलाम
वक्त का हर शै पर राज ।

एक नयी दिशा बने, एक नया वातावरण बने, एक नया सूर्योदय हो, मैं निराश नहीं हूँ।

" रात जितनी ही संगीन होगी,
सुबह उतनी ही रंगीन होगी,
रात भर का है मेहमां अन्धेरा,
किसके रोके रूका है सवेरा ।

आईए हमलोग कल सेबेरे की ओर चलें। लालू जी, अगर आप कल एक घंटा भाषण देंगे तो आप अपने दिल की जजबात को प्रकट करें, कि हम बदल गए। आप बदले हुए हैं कुछ। लेकिन पूरे नहीं बदले हैं, कुछ बदले हैं, लेकिन पूरे नहीं बदले हैं। दिल खोलके बदल जाईए और जो एक लाख रूपया रामनवमी के भिकटिम को दिया है, उनको नौकरी देने का वादा भी किया

(94)

है उसको तुरंत देंगे तभी पता चल जायेगा कि आप बदले हैं कि नहीं। कल आप बोलेंगे। सभापति महोदय, आपका इशारा हो रहा है और समझदारों को इशारा समझना चाहिए।

" इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो"

धन्यवाद।

श्री जगत नारायण सिंह: सभापति महोदय, आज मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, असेम्बली चुनाव से पहले कुछ लोगों द्वारा यह भ्रमित किया जा रहा था कि बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। महोदय, जब चुनाव हुआ तो चुनाव के समय में ऐसा लग रहा था कि चीन और भारत के बीच लड़ाई हो रही है। पूरे भारत में विपक्षी लोग, प्रधानमंत्री, श्री लाल कृष्ण आडवानी जी, सबों ने 50वों हेलीकॉप्टर से ज्यादा लेकर बिहार के हर कोने-कोने का दौरा शुरू कर दिया था। आप सबों को जानकारी है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा था कि बिहार में जंगलराज कायम हो गया है। हमारे मिडीया के लोगों ने भी लालू-राबड़ी सरकार के विरोध में हर जगह चर्चाएं शुरू कर दिया था। यह आपलोगों को जानकारी है। महोदय, लेकिन बिहार की जनता ने यह साबित करके दिखला दिया कि इतने विरोध के बावजूद भी लालू-राबड़ी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और अभी इसी पार्टी की सरकार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सरकार 5 साल तक अपने कार्यकाल को पूरा करेगी। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि संविधान बनाया जाय जिसमें पिछड़ों वर्गों को संविधान में आरक्षण दिया जाय लेकिन उसे ताख पर रख दिया गया।

(क्रमशः)

सभापति (श्री गणेश प्र0 यादव): आप अपने विषय पर बोलते तो ज्यादा ठीक रहता ।

श्री जगत नारायण सिंह : मैं आ रहा हूं उसी विन्दु पर महोदय, मैं कहना चाहताहूं कि बहुत से लोगों ने आवाज बुलंद किया था कि मंडल कमीशन को लागू किया जाए लेकिन बार-बार उसको ताक पर रखने का काम किया गया । हमारे बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री स्व0 कर्पूरी ठाकुर जी ने भी मंडल कमीशन लागू करने की बात कही थी लेकिन उसे भी कुचल देने का काम कियागया ।

सभापति (श्री गणेश प्रसाद यादव): माननीय सदस्य, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के समय में तो मंडल कमिशन आयाही नहीं था ।

श्री जगत नारायण सिंह : सभापति महोदय, उस समय उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागूकरने की बात कही थी ।

श्री रमई राम(मंत्री): सभापति महोदय, माननीय स्व0 कर्पूरीठाकुर जी के समय में मंडल कमीशन की शुरुआत हो गयी थी ।

श्रीजगत नारायण सिंह: सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 1990 में बिहार के मुख्य मंत्री हुए लालू प्रसाद जी, वेसामाजिक न्याय के योद्धा हुएथे । उन्होंने मंडल कमीशन को लागू कर गरीबों के हितों की रक्षा करने का काम किया । आप सबों को मालूम होगा, जानकारी होगी कि आज बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार है और गरीबों को मान-सम्मान देने वाले लालू - राबड़ी की सरकार चल रही है ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य बोल रहे हैं, खास कर बोल रहे हैं कि बिहार में बहुत ज्यादा साम्प्रदायिक दंगा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं आंकड़ा दे रहा हूं कि दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में सबसे कम अपराध हो रहे हैं जिसका उदाहरण है कि मध्य प्रदेश में 12 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 11 प्रतिशत, राजस्थान में 10 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 9 प्रतिशत और बिहार में 6 प्रतिशत ।

टर्न-38/राहुल/13. 7. 2000

सभापति महोदय, औरंगाबाद और मियांपुर नरसंहार की बात हमारे माननीय विपक्षी दलों के लोग बोल रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मंत्री माननीया राबड़ी देवी जी ने सभी विपक्षी दलों कोबुला कर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का काम किया था लेकिन क्या कारण है कि हमारे विपक्षी दल के माननीय नेतागण इसमें साथ नहीं दिए जब कि संविधान में विपक्ष को भी कम अधिकार नहीं होता है और सरकार को सहयोग देने का उनका अधिकार है, न कि विरोध करने का। जो नरसंहार हुआ उसके लिए वे लोग अलग से बैठक किए कि क्या बात थी, मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहताहूं।

सभापति महोदय, विकास की बात हो रही है। कौन सा विकास नहीं हुआ ? मैं कहना चाहताहूं कि इन्दिरा आवास योजना पहले भी था। लालू - राबड़ी सरकार के पहले भी कुछ-कुछ जगहों पर बना था लेकिन इसमें सफेदपोश लोग अभिकर्त्ता बने हुए थे। वे हरिजनों का पैसा लूट कर खा जाया करते थे लेकिन लालू-राबड़ी की सरकार ने, आज जो हरिजनों का मकान बन रहा है इन्दिरा आवास योजना के तहत, उन्हें ही अभिकर्त्ता बनाया गया, उनको ही मालिक बनाया गया, उनको ही पैसा दिया गया ताकि अपने काम को अपने हाथ से ठीक से कर सकें। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करताहूं।

सभापति (श्री गणेश प्रसाद यादव): माननीय सदस्य, श्री मो० हुसैन अंसारी जी, आप बोलिए।

श्री मो० हुसैन अंसारी: सभापति महोदय, आज बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की हुकूमत है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरे बिहार में जो पदाधिकारी जहां पदस्थापित हैं, वे ही वहां के मालिक हैं। किसी को भी जरा सा डर सरकार का या किसी का नहीं है।

..../-

(97)

टर्न-38/राहुल/13.7.2000

उनको इस बात का जरा भी भय नहीं है कि वे कौन सा काम कर रहे हैं। अभी गत सप्ताह हमलोग अपने पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री शिबू सोरेन जी के साथ पार्टी के सभी विधायक लोग धनबाद, गिरीडीह, देवघर, दुमका जिला का दौरा करने गए थे। धनबाद जिला के टोरापुर के बगल में केलीपाड़ा एक बस्ती है जहां बीस एकड़ की एक सरकारी जमीन है जिस पर 1962-63 से ही वहां एक व्यवसायी, उस बीस एकड़ जमीन से पत्थर तोड़ने के लिए लिया था, 1975 तक पत्थर तोड़ा और 1984 में नारायण दास के आदमी ने सरकारी जमीन को अपने नाम से करा लिया। उसका रसीद कटवा लिया।

क्रमशः

टर्न-39/मधुप/13.7.2000

श्री मो0 हुसैन अंसारी : क्रमश: ...... पुन: एक आदमी ने उसमें दो एकड़ जमीन का जाली पट्टा बनवाकर उस स्थान पर कब्जा कर लिया, जिस स्थान पर वहाँ के आदिवासी लोगों ने परम्परागत ढंग से पूजा स्थल बनाया था, सरनास्थान था। महोदय, दोनों में मुकदमा हुआ, नारायण दास और दूसरे पक्ष के बीच में, चूँकि जमीन सरकार की थी वह केस डिसमिस हो गया कि यह जमीन सरकार की है, लीज सरकार ने दिया था, आपका पट्टा गलत था, न्यायालय में वह केस खारिज हो गया। 1975 में .. वहाँ के सी0ओ0 ने उस पट्टा पर रसीद काट कर म्युटेशन कर दिया जबकि नियम है कि बगैर डी0सी0 के आदेश के रसीद नहीं कट सकता है। इस साल आज से दो-तीन माह कबल जिस स्थान पर आदिवासी लोग परम्परागत ढंग से पूजा कर रहे थे, वहाँ प्रशासन के दबाव से चहारदीवारी :: दिया जाने लगा। अभी भी वहाँ पुलिस का पहरा है और पुलिस के पहरे में चहारदीवारी का निर्माण वहाँ हो रहा है। पूरे आदिवासी इलाके में इसका विरोध हुआ, उसके चलते बहुत लोग जेल में हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि वहाँ जो आदिवासियों का परम्परागत पूजा-स्थल है, आदिवासी वहाँ जिस दिन से बसा है, तभी : से वह उनका पूजा स्थल है, उसको पूजा स्थल ही रहने दिया जाय और प्रशासन के : . जरिये पुलिस जो वहाँ ज्यादती कर रही है, पुलिस को वहाँ से हटवाया जाय।

महोदय, गिरिडीह जिला के .. कुछ लोग जिन पर पुलिस द्वारा ज्यादती की गयी थी, 8 तारीख को सारे गाँव के लोग जिसमें खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, मेरे समक्ष आये और कहा कि किस तरह से पुलिस ने बेरहमी से पीटा है, बाल-बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस का जुल्म शरीफ लोगों पर ढाया गया जबकि वहाँ आतंकवादियों और पुलिस के बीच झगड़ा था। पुलिस शरीफ आदमियों को जबरन मजबूर कर .. रही है, उनको पीटा जा रहा है।

टर्न-39/मधुप/13.7.2000

॥ व्यवधान ॥

महोदय, संथाल परगना या जहाँ कहीं भी गोचर जमीन है, उसको लीज पर नहीं दिया जा सकता है लेकिन साहेबगंज जिला में वहाँ के डी०सी० ने गोचर जमीन को लीज पर दे दिया जिसपर अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, माँग करता हूँ कि शीघ्र उसका लीज खत्म किया जाय और उसके लिये दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई किया जाय।

॥ लाल बत्ती ॥

सभापति महोदय, अकलियत के लिये होस्टल बनाने की घोषणा की गयी थी। इस सरकार ने यह घोषणा किया था कि हर जिले में हम अकलियत के लिये होस्टल का इन्तजाम करेंगे लेकिन जब मैंने मंत्री महोदय, मंजूर आलम साहब से पूछा कि हमारे जिले के लिये इस संबंध में क्या हो रहा है तो उन्होंने बताया कि मार्च के पहले 20 लाख रूपया होस्टल के लिये और 4 लाख रूपये कब्रिस्तान के लिये दिया गया, वह पैसा खर्च नहीं हो सका और सरेन्डर हो गया। कम से कम एक विधायक होने के नाते जब हमलोग कुछ कहते हैं तो कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिये। पता नहीं वहाँ जो पैसा गया, उसका क्या हुआ? ॥ व्यवधान ॥

सभापति ॥श्री गणेश प्रसाद यादव॥ : माननीय सदस्य, अब आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री मो० हुसैन अंसारी : महोदय, एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। महोदय, पूरे बिहार में आज अगर किसी का सबसे बुरा हाल है तो वह बिहार में बुनकरों का हाल है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि सारे बुनकर इस बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के वोटर माने जाते हैं, उन्हीं के सपोर्टर हैं। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि सरकार उनके कल्याण के लिये योजना चलाये। धन्यवाद।

श्री सुल्तान अहमद: माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जबसे माननीया मुख्यमंत्री मोहतरमा राबड़ी देवी गद्दी पर बैठी हैं तबसे हर हफ्ते एक बैठक के अलावा स्पेशल बैठक होती आ रही है। माननीया मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं, वह सराहनीय हैं। इसका प्रमाण है कि जिस राज्य का मंत्रिपरिषद नियमित रूप से बैठक करेगा, उस राज्य का काम सुचारू रूप से होगा। समय-समय पर मंत्रिपरिषद विकास के कार्यों की समीक्षा करती है और माननीया मुख्यमंत्री खासतौर से विधि व्यवस्था और विकास के कार्यों की समीक्षा स्वयं करती हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बिहार राज्य में विगत वर्षों में अपराध की घटनाओं में कमी आयी है। महोदय, बिहार की बढ़ती हुई आबादी, लखनऊ के बाद इस राज्य की आबादी सबसे अधिक है। जनसंख्या अधिक हो गई है लेकिन अपराध की घटनायें कम हो रही हैं।

सभापति महोदय, अपराध के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रणालय के क्राइम्स रेकर्ड ब्यूरो 97 के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों की अपराधों की संख्या इसप्रकार है, मध्यप्रदेश-12%, राजस्थान 10प्रतिशत, उत्तरप्रदेश 9परसेंट, तमिलनाडु 8परसेंट, कर्नाटक 7परसेंट, गुजरात 6परसेंट, आंध्रप्रदेश 6परसेंट, केरल 6परसेंट और बिहार 6परसेंट, अन्य राज्यों में कुल 36परसेंट है। बढ़ते हुए जनसंख्या के आधार पर अपराध की स्थिति नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्यूरो के अनुसार इसप्रकार है, दिल्ली 225, राजस्थान 350, केरल 300, मध्यप्रदेश 275, मिजोरम, गुजरात, कर्नाटक 220 और बिहार 10। महोदय, वर्ष 1997-98 में हत्या, डकैती, रेल-डकैती, बलात्कार आदि अपराधों की घटनाओं में कमी हुई है। अपराध नियंत्रण अधिनियम एवं राष्ट्रीय अधिनियम के तहत जिला पदाधिकारी को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ-ही इस अधिनियम के तहत अपराधियों

(1011)

पर कार्यवाई की जा रही है। पूरे राज्य में बन्दूक कारखाना बरामद किये गये हैं। वर्ष 1998 में ऐसे 91 बन्दूक के कारखाना पकड़े गये हैं।

....क्रमशः...

श्री सुल्तान अहमद : (क्रमश:) और अपराधियों को धर-पकड़ की गई । राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की घटनायें काफी बढ़ी है ।

सभापति(श्री गणेश प्रसाद वर्मा): माननीय सदस्य,आप लिखित नहीं पढ़े ।

श्री सुल्तान अहमद : सभापति महोदय, मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं :-

" हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती । "

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय सभापति महोदय,आज जिस महकमे पर विचार-विमर्श है । सच कहा जाय तो आज स्वीकृत जो राजनीति सत्ता है, आज का वस्तुत: वाद-विवाद उसी विषय वस्तु पर केन्द्रीत है । यह राजनीति सत्ता इस राज्य के जनता के लिए कानून सम्मत कार्य कर रही है ? इसकी शुरूआत हम एक खास बात से करना चाहेंगे ।

सभापति महोदय, बिहार के नक्शे में एक जिला है सिवान । इस सिवान जिले के बारे में खुफिया विभाग ने जो रिपोर्ट तैयार की है, जो टाईम्स ऑफ इंडिया,प्रभात खबर एवं कई अखबारों में निकला है कि सिवान जिला में जिला-धिकारी का कोई आदेश नहीं चलता है । उस सिवान जिला में राजद के एक दबंग नेता हैं, जो जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठते हैं । एक बार इनकी बात मानने से जिलाधिकारी ने इन्कार कर दिया तो उसके कार्यालय के दिवाल पर 50 गोलियां चली ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, ये बैठें, इनकी बारी आयेगी तो ये बोलेंगे ।

मैं कह रहा हूं, यह कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है,सरकार के द्वारा जो गठित खुफिया विभाग है और यह निशान कोई कागज पर नहीं हैं,आपके डी.एम. के कार्यालय के पास जो दिवाल है,उस पर 50 गोलियां चली । आप जानते हैं, वहाँ की जनता ने अब डी.एम. के कार्यालय में जाना बन्द कर दिया है,क्योंकि कोर

(103)

अब डी.एम. या डी.एस. के स्टाफ रिसीव नहीं करते हैं, वे दबंग नेता रिसीव करते हैं । हम यह बात कहना चाहते हैं, अगर प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का मंत्रिमंडल समन्वय समिति ने निर्णय लिया है तो बेहतर है कि आप विकेन्द्रीकरण नीचे तक कर डालिए । जो विकेन्द्रीकरण आप सिवान में कर रखा है, वैसा विकेन्द्रीकरण आप तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में ऐसे बाहुबलियों का कर दीजिए तो अलग से विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं होगी ।

श्री अवध बिहारी चौधरी (मंत्री): माननीय सदस्य, आप गलत बोल रहे हैं ।

श्री महेन्द्र प्र0 सिंह : सभापति महोदय, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो इसकी चुनौती देता हूं । मैं चुनौती देता हूं सरकार और सरकारी पक्ष के लोगों को, अगर सरकार को हिम्मत है तो वे दिवालों का सर्वेक्षण करायें । आखिर डी.एम. के कार्यालय के दरवाजे पर गोलियों का निशान कैसे उगा ?

(व्यवधान)

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, नामधारी जी जब अपनी बात शुरू की थी तो कहा था कि सत्ता में कोई प्राधिकार हो तो यह बेहतर बात होती अराजकता के खिलाफ लड़ने के लिए लेकिन यह प्राधिकार ऐसा हो, जो प्राधिकार के परिधि में शून्य ही शून्य हो तो यह प्राधिकार महाशून्य को जन्म देती है और महाशून्य के जन्म से सिर्फ अराजकता पैदा होती है । यह अराजकता कैसे पैदा होती है, मैं इसका हरेक विभाग का उद्धरण दे सकता हूं । बिहार में मानवाधिकार को लेकर, पुलिस के जनविरोधी आचरण को लेकर बड़ी चर्चा होती है लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप अगर उसके बजट पर गौर करें तो हर थाने में थानेदार को पेट्रौलिंग करने के लिए आप कितने ईंधन की आपूर्त्ति करते हैं लेकिन आप उनको कहते हैं कि सड़कों पर गश्ती करें, गांवों में गश्ती करें लेकिन इसके लिए ईंधन कहां से आयेगा ? स्वाभाविक है यह तेल आयेगा लोगों का जेल

काटने से, लोगों के गर्दन पर बन्दूक का कुन्दा रखने से, इसके जरीये आता है तेल। इससे मानवाधिकार नष्ट होता है, लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार खतम होता है। अंग्रेजों के जमाने के सल्तनत का जो तरीका चला आ रहा है, आज भी उसके फेर-बदल की जरूरत हम महसूस नहीं करते हैं। महोदय, दलितों और गरीबों की यह सरकार है, यह भी इस पर गौर नहीं करती है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप देखें कि कलक्टर के यहां कितनी गाड़ियां हैं ;

(क्रमशः)

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह(क्रमशः): आप देखिए एम0पी0 के पास कितनी गाड़ियां है, गृह विभाग के पास कितनी गाड़ियां है। थाने में आपको गाड़ी की कमी मिलेगी।अगर मिलेगी भी तो ठेलेने वाली गाड़ियां ही मिलेगी। थाना के लोगों को ही घटनास्थल पर जाने की जवाबदेही होती है। समन्वय विभाग को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए । कामों के प्रगति की स्थिति क्या है? इस पर एक नजर डाला जाय। यह वित्तीय वर्ष का चौथा महीना है। इस चौथे महीने में राज्य का बजट चाहे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का हो या अन्य विभाग हो चाहे एम0पी0, एम0एल0ए0 को दिये जाने वाली विकास की राशि हो कहीं इन पैसे से काम शुरू नहीं हुआ है। व्यवहार में समन्वय वित्तीय वर्ष शुरू होता अक्तूबर से । वस्तुतः अप्रील से वित्तीय वर्ष की शुरूआत होती है लेकिन व्यवहार में ये वित्तीय वर्ष की शुरूआत करते हैं अक्तूबर से । हम कह रहे हैं वर्ष में तीन महीना चार महीना ही काम होंगे तो आखिर आप किस दम पर विकास की बात करेंगे । विकास के लिए, कल्याण के लिए जो राशि देते है उसका शतप्रतिशत उपयोग, खर्च कैसे हो पायेगा ?काम करावाना दूसरी चीज है और अंधेरे में तीर मारना दूसरी चीज।

सभापति(गणेश प्र0यादव): माननीय सदस्य आपका समय हो गया।

महेन्द्र प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, मैं आसन से इजाजत चाहूंगा। मेरे लिए इतना संकीर्ण मत बनिये । आपका मिनट कितने सेकेंड का होता है वह मेरे लिए भी रहने दीजिए।

सभापति(श्री गणेश प्रसाद यादव) इन्हीं मिनट के आधार पर मैं आपको बतला रहा हूँ ।

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, आदिवासियों के कल्याण की बात होती है। राज्य सरकार की एक योजना है माडा योजना। आप जानते हैं 1992 में इनके कल्याण आयुक्त ने एक परिपत्र जारी किया जिसका पत्रांक 655 दिनांक 1-7-92 है इसके द्वारा सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, कि जो माडा से संबंधित जिले हैं निर्देश दिया गया कि मेसर्स इंडिया एग्रीकल्चर कम्पनी जो कंकड़बाग में है सारा सामान वहीं से खरीदा जाय। जिला में टेंडर नहीं होता है वहीं से सारे सामान खरीदे जाते हैं । आज जब मंत्री महोदय से अध्यक्ष महोदय ने जानना चाहा कि किस कम्पनी से सामान आया तो उस कम्पनी का नाम मंत्री महोदय नहीं पढ़ पाये, ऐसी-ऐसी जगहों से सामानों की सप्लाई होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। सभापति महोदय, गिरिडीह जिला की मैं बात कह रहा हूँ, गिरिडीह जिला के 13 गांव में बांस लगाना था । एक बांस पर आधा बोरा खाद देने की बात थी। 1500

बांस लगा लेकिन एक बांस भी नहीं उगा । सभापति महोदय, आश्चर्य की बात तो तब होती है उस परिपत्र में इस बात का भी उल्लेख था कि जब एडवांस राशि देंगे तो 5 प्रतिशत दाम कम लेंगे । सारे जिले से राशि शतप्रतिशत मिली लेकिन 5 प्रतिशत दाम की कमी नहीं हुई। सभापति महोदय, पुलिस प्रशासन की आज क्या स्थिति है, सिर्फ एक नमूना मैं देना चाहता हूँ । गिरिडीह जिला में बगोदर थाना है। एक ही परिवार के पिता, पुत्र, सगे भाई पर रेफ का मुकदमा दर्ज हुआ । पुलिस का हथियार छीना गया था इसलिए वहां के ग्रामीणों ने विरोध में थाना बंद कर दिया था । सबक सिखाने के उद्देश्य से एक ही परिवार के 6 लोग बाप बेटा, सगे भाई पर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया । नीचे से ऊपर तक इसके जांच के लिए गुहार की गयी लेकिन जांच नहीं हुई । दूसरा सबक सिखाने के लिए बेगम यादव जो जेल में है उसके घर में कुर्की जप्ती की गयी । मजिस्ट्रेट ने जांच में इस बात की पुष्टि कर दी कि जब वह जेल में था तो कुर्की जप्ती की गयी। वह सरेंडर नहीं किया था पुलिस उसको गिरफ्तार कर के ले गयी थी । जांच पर नीचे से ऊपर तक रिपोर्ट लिखी गयी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई । आखिर समन्वय किस चीज का करती है सरकार।

(क्रमशः)

(107)

टर्न-43/13.7.2000

टलनैन

क्रमशः

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि समन्वय कहां है, जिला योजना से कूआं बनता है 26 हजार रूपये में 10/40 फीट का और पी.एच.ई.डी. बनाता है 52 हजार रूपये में 10/40 फीट का और एक ही जमीन पर। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जब वह अपना जवाब दें तो इस चीज के बारे में भी अपना वक्तव्य दें। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रहलाद यादव: अध्यक्ष महोदय, आज जो मंत्रिमण्डल सचिवालय एंव समन्वय विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। महोदय, जिसमें गुण होता है उसमें अवगुण भी होता है। सरकार ने जिस रूप में आम जनता तक हर मामले में चाहे विकास की बात हो चाहे सहयोग की बात हो सभी में अच्छी प्रगति की है। महोदय, जहां तक सचिवालय की बात है हम जनप्रतिनिधि किसी शिकायत को किसी तरह से लिख कर देते हैं तो उसपर कार्रवाई होनी चाहिये लेकिन इस पर अमल नहीं होता है।

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, एक महिला सदस्या हैं जो विपक्ष में बैठी हुई हैं, एक दिन भी उस दल के लोगों ने उस महिला को बोलने का मोका नहीं दिया।

श्री प्रहलाद यादव: मैं कहना चाहता हूं महोदय कि जनप्रतिनिधि जन कल्याण के लिये जन-हित की बात के लिये, चाहे जिला हो चाहे सचिवालय हो कहीं भी जाता है तो उसपर ध्यान दिया जाना चाहिये, उसपर अमल होना चाहिये। महोदय, मैं अपनी एक घटना को बताना चाहता हूं कि विगत शनिवार को मैं अपने गांव गया था और वहां के एस.पी. ने अपने मुन्शी से स्टेशन डायरी

टर्न-43/13.7.2000

हसनैन

मैं दर्ज करवाया कि माननीय विधायक अपने क्षेत्र में घूमने के लिये गये हैं, कोई घटना हो जायेगी । इस तरह से स्टेशन डायरी में अंकित करवाया जाता है । अध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाकर जनता के हित के लिये प्रयास करता है, उनकी सहायता के लिये जाता है और इस तरह का आरोप लगाना जनप्रतिनिधि के विरूद्ध जनतंत्र में अच्छी बात नहीं है ।

श्री श्रीभगवान सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष: कोई व्यवस्था नहीं है । आप बैठिये ।

श्री श्रीभगवान सिंह: वहां के एस.पी. को तत्काल हटाया जाय ।

टर्न-४४/ अशोक
१३-७-२०००

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, मैं बतलाना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में विकासकार्य हो रहा था, जनोपयोगी काम है, जनोपयोगी उस काम को डी०एम० ने ड्रोप किया है, इस तरह से खास करके वहां डी०एम०, एस०पी० गये हैं एम०एल०ए० से लड़ने के लिये, लड़ने के लिये गये हैं, इस तरह का जुल्म और अन्याय हो रहा है महोदय, मैं बतलाना चाहता हूँ कि किस रुप में इस लोकतंत्र में एक जन-प्रतिनिधि काम कर सकता है, यह स्थिति है महोदय। महोदय, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं, उनको कहने दीजिये। सरकार का जब वाब देने का वक्त आयेगा तो उसका जवाब देंगी। बोलने दीजिये, पहली बार बोल रहे हैं।

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, मेरे अंगरक्षक को लौटा लिया गया, चिट्ठी पर लिखा गया था कि यादव और भूमिहार को छोड़कर अंगरक्षक दिये जायेंगे, यह स्थिति है, दो महीना से अंगरक्षक नहीं दिया गया है, इस तरह से जलील किया गया था जन-प्रतिनिधि को, इस स्थिति में वह क्षेत्र में जाकर क्या काम कर सकता है? यह स्थिति है महोदय, यह स्थिति है महोदय।

अध्यक्ष : आगे आप अपने क्षेत्र की बात बोलिये, क्षेत्र की समस्या के बारे में बोलिये।

श्री प्रह्लाद यादव : मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से जन-प्रतिनिधि को प्रताड़ित किया जायेगा तो जनता की सेवा कैसे कर सकता है- यह स्थिति है महोदय। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो स्थिति माननीय सदस्यों के साथ हो रही है, इस स्थिति में अगर गंभीरता से नहीं सोचेंगे तो निश्चित रुप से लोकतंत्र के लिये एक जबर्दस्त कलंक होगा, इसलिये मैं आपसे मांग करता हूँ कि इस पर गंभीरता से सोच कर, इस पर विचार करके और इस तरह का जो समन्वय है, समन्वय को जो खंडित करना चाहते हैं, यह नहीं होना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

टर्न-४४ / अशोक
१३-७-२०००

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राजन ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ठाकुर जी , आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री गणेश प्रसाद यादव : माननीय सदस्य ने जो बात कही है , वह बहुत ही सिरियस है, जब विधायक क्षेत्र में जाय . . . . .

अध्यक्ष : सरकार इसको गंभीरता से लेगी ।

श्री गणेश प्रसाद यादव : अमुक अंगरक्षक नहीं दिया जायेगा, अमुकजाति का अंगरक्षक नहीं दिया जायेगा . . . . .

अध्यक्ष : सरकार इसको गंभीरता से लेगी ।

श्री राजेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, आज मंत्रिमंडल समन्वय प्रशासन पर चर्चा चल रही है, माननीय सदस्य श्री इन्दर सिंह नामधारी जी जिस वक्त अपने दिल का उद्गार प्रकट कर रहे थें औरों की तरह मैं भी इनकी बातें गौर से सुन रहा था, लेकिन माननीय सदस्य श्री नामधारी जी की बातों में जो दर्द था, चिन्ता थी जिसे वे प्रकट कर रहे थें मुझे तरस आ रहा था नामधारी जी पर- साथ रह कर , अलग हटकर तब भी इन्होंने अभी तक सच्चाई को नहीं पहचाना और इसलिये अंधा के आगे रोये, अपना दीदा खोये यह कहावत चरितार्थ हो रही थी ।

अध्यक्ष : यहां न कोई अंधा है और न कोई बहरा है। आप शब्दों का ठीक से प्रयोग कीजिये, संसदीय भाषा में बोलिये ।

श्री राजेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, यह कहावत है और संसदीय भाषा में ही है । इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि सच्चाई आज इस रुप में है हमारे सामने है । इसलिये अध्यक्ष महोदय क्या स्थिति है हमारे मंत्रिमंडल की, अभी चर्चा हुई कि मंत्रिमंडल कुत्ता का शरीर है और प्रशासन उसका दुम है, प्लोटो की प्रस्तुत युक्ति से माननीय सदस्य

(////

टर्न-४४ / अशोक
१३-७-२०००

श्री नामधारी जी ने इस बात की चर्चा की ।

अध्यक्ष : माननीय नामधारी जी ने "मुँह" कहा था, "शरीर" नहीं कहा था । उन्होंने मुँह कहा था, मैं सुन रहा था ।

श्री राजेन्द्र राजन : प्लोटो की युक्ति इन्होंने दुहराई थी, मैं कहना चाहता हूँ कि आज मंत्रिमंडल अगर घोड़े का सवार है ... ..

श्री शकुनी चौधरी (मंत्री) : जिस भाषा का इस्तेमाल माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राजन ने किया या तो ये वापस लें या सदन से माफी माँगें ।

अध्यक्ष : मैंने कह ही दिया गलत है, गलत करार दिया है । मैंने कह दिया कि ऐसी भाषा का उपयोग मत कीजिये ।

(1111

टर्न-४४ / अशोक
१३-७-२०००

श्री नामधारी जी ने इस बात की चर्चा की ।

अध्यक्ष : माननीय नामधारी जी ने "मुंह" कहा था, "शरीर" नहीं कहा था । उन्होंने मुंह कहा था, मैं सुन रहा था ।

श्री राजेन्द्र राजन : प्लेटो की युक्ति इन्होंने दुहराई थी, मैं कहना चाहता हूँ कि आज मंत्रिमंडल अगर घोड़े का सवार है ...

श्री शकुनी चौधरी (मंत्री) : जिस भाषा का इस्तेमाल माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राजन ने किया या तो ये वापस लें या सदन से माफी मांगें ।

अध्यक्ष : मैंने कह ही दिया गलत है, गलत करार दिया है । मैंने कह दिया कि ऐसी भाषा का उपयोग मत कीजिये ।

।व्यवधान।

श्री लालू प्रसादः अध्यक्ष महोदय, गाली देकर माफी मांगना यह भी एक फैशन है और यह हाइली औबजेक्शनेबल है । दूसरे को गाली देना और मंत्रिमंडल के बारे में कहना कि मंत्रिमंडल कुत्ता होता है अच्छी बात नहीं है ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, राजन जी, अच्छी भाषा का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री लालू प्रसादः राजन जी, आप भी उसी इंतजार में बैठे हैं जिसको आप कुत्ता कह रहे हैं।

अध्यक्षः कटु से कटु बात को भी अच्छी भाषा में बोलिये ।

श्री राजेन्द्र राजनः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बत कहना चहता हूँ, मेरी बात सुनी जाय मंत्रिमंडल अगर घोड़े पर सवार है और उसमें शासन घोड़ा है और सवार इतना कमजोर हो कच्चा हो और घोड़ा समझ जाय कि सवार कैसा है तो कभी भी सवार को पीठ पर नहीं रहने देगा और आज की स्थिति इस मंत्रिमंडल की वही है। कच्च सवार है घोड़ा पटक रहा है । इसलिये आज सही मायने में इसबात की चर्चा करना चाहता हूँ कि इस मंत्रिमंडल से बिहार को उम्मीद है हम समझते हैं वह उम्मीद आज पूरी होने को नहीं है। इसलिये १९५२ में जब मंत्रिमंडल का आकार ९ से १४ किया गया तो उस वक्त के माननीय सदस्य, स्व० रामानंद तिवारी जी डा० श्रीकृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल को चुनौती देते हुये कहे थे कि गरीब बिहार ९ से १४ मंत्रिमंडल के भार को नहीं संभाल सकता है। और आज २००० ई० में हम ७९ के मंत्रिमंडल का भार ढो रहे हैं ।इसमें मजबूरियां चाहे जो हो अलग बात है लेकिन आज बिहार की स्थिति क्या हम कहना चाहते हैं कि आज इस बढ़े हुये आकार से बिहार का हित नहीं होने वाला है ।

श्री शकुनी चौधरी(मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट ऑफ आर्डर पर खड़ा हूँ। हम आपके माध्यम से कहना चहते हैं कि इतिहास साक्षी है कि जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था देश तो उस मय कम्युनिस्ट उसके दोस्त बने हुये थे । आज समाज में जितनी कुरीतियां हैं वह सी०पी०आई० लोगों की देन है ।

श्री राजेन्द्र राजनः अध्यक्ष महोदय, हमारे शकुनी चौधरी जी सत्ता की कुर्सी से चिपक कर जीना चाहते हैं, इतिहास की बात न करें अच्छा होगा ।

अध्यक्षः आप अपनी बात कीजिये, मात्र दो मिनट का समय है ।

श्री राजेन्द्र राजनः अध्यक्ष महोदय, जिनको तीन मिनट देना चाहिये उनको १२ मिनट का समय दिया गया है इसलिये हमको भी समय दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, कल इसी सदन में घोषणा की गयी कि जो माननीय सदस्य यहां आर्म्स लेकर आयेंगे उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी। यह स्वागत योग्य कदम है। हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि सरकार अपनी उस घोषणा को अगर इमानदारी से अमल करना चाहती है तो क्या यह आदेश देगी कि तमाम सरकारी आवासों पर जहां मंत्रियों और विधायकों का आवास है वहां हथियार अगर पकड़ा जाय और वहां अपराधी पकड़े जायेंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त की जायेगी उन्हें मंत्रिमंडल से निकाला जायगा ? मैं कहना हूं कि यदि ऐसा हो तो बिहार की तीन हिस्सा बीमारी ठीक हो जायेगी।

श्री लालू प्रसादः सरकार को कोई अधिकार नहीं है किसी की मेम्बरी समाप्त करने का, थोड़ी जानकारी रखिये। यह पूरे सदन को अधिकार है।

श्री सुशील कुमार मोदी ने०वि० दल): अध्यक्ष महोदय, सदन को भी अधिकार नहीं है मेम्बरी समाप्त करने का।

श्री लालू प्रसादः हाऊस इज ए कोर्ट, यह न्यायपालिका भी है और यह सजा भी दे सकता है ७ दिनों तक और मेम्बरी समाप्त भी की जा सकती है। यही नहीं कौन पोशाक पहन कर आना है वह भी निर्धारित है। क्या कपड़ा, कैसा चश्मा लगाना है वह निर्धारित है। थोड़ा पढ़िये, जानकारी रखिये। जब कोई घर पर चला जायेगा हथियार लेकर और जब कोई दुश्मन चाहे कोई एम०एल०ए० ही चला जाय तो क्या उसकी मेम्बरी खत्म करेगी सरकार ?

श्री राजेन्द्र राजनः अध्यक्ष महोदय, मैंने कल की घोषणा को देखते हुये कहा। अगर आप अपराध पर नियंत्रण चाहते हैं, स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं, बिहार को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं तो उन आवासों पर जहां हथियार हैं और अपराधी रहते हैं और जिन पर वारंट है उनकी पहचान करायें और गिरफ्तारी हो जाय तो एक बड़ी समस्या हल हो सकती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इनके दल के लोगों द्वारा बहुत से सरकारी विधायकों के आवास पर कब्जा किये गये हैं क्या आप उनको खाली कराना चाहते हैं। मैं प्रेसीडेंट चैम्बर में रह रहा हूं आज वहां के अधिकांश फलैट इनके लोगों द्वारा मर्द ही नहीं औरतों द्वारा कब्जा किया गया है और दुनिया का कोई ऐसा धंधा नहीं बचा है जो वहां नहीं होता है। अगर आप इमानदारी से चाहते हैं कि हम स्वच्छ प्रशासन दे सकें तो आप ऐसे आवासों पर कब्जा हटाने के लिये कोई कदम उठायेंगे,

अध्यक्ष: आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राजन: मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब नामधारी जी बोल रहे थे तो लालू जी सकुचा रहे थे और सकुचाहट में स्वाभाविकपन था इसलिये कि आज एक संवैधानिक सरकार है और जिसका नेतृत्व राबड़ी जी के हाथों में है और मैं चाहता हूं कि इस संवैधानिक सरकार में राबड़ी जी की सरकार में श्री रमई राम जी को उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करवा दीजिये।

अध्यक्ष: अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, देख लीजिये, राजन जी कितने ज्ञानी हैं। उप मुख्यमंत्री का प्रावधान किसी संविधान में नहीं है ओथ कराने का। मंत्री का ओथ होता है। क्या उल्टा पढ़ा रहे हैं रमई भाई को।

अध्यक्ष: वाद विवाद यहीं समाप्त हुआ। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिये जायेंगे।

श्री रामेश्वर प्रसाद के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर श्री गणेश प्रसाद यादव जी को पूरक पूछना है प्रदूषण नियंत्रण पर्षद वाले पर क्योंकि उनका भी उस पर सिगनेचर है।

सर्वश्री रामेश्वर प्रसाद, भाई वीरेन्द्र एवं अन्य दो सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना पर पूरक क्रमशः ...

श्री गणेशप्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि लोक उद्यम ब्युरो ने अपनी चिट्ठी निकालकर सभी ऐसे बोर्ड और निगमों को यह हिदायत दी थी कि ५८ वर्ष के बाद किसी पद पर उनकी पुर्नियुक्ति नहीं की जाय लेकिन इसका उल्लंघन करते हुये प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष ने ५८ वर्ष की अवधि पार व्यक्तियों को नौकरी दी है ?

श्री मनोज कुमार यादव(मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री गणेश प्रसाद यादव जी ने जिन बातों का जिक्र किया है उसकी जांच करायेंगे और तदोपरांत कार्रवाई करेंगे।

श्री गणेश प्रसाद यादव: महोदय, यह चिट्ठी तीन साल पहले निकली हुयी है, फिर जांच किस चीज की होगी ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है जो आप कह रहे हैं उस आधार पर देखेंगे।

(1157)

श्री गणेश प्रसाद यादवः जांच कर ऐसे व्यक्तियों को कितने दिन में हटा दीजियेगा ?

मंत्री जी को पत्र की प्रतिलिपि नहीं है तो मैं उसको हस्तगत करा देता हूं।

श्री मनोज कुमार यादव(मंत्री): पत्र को उपलब्ध करा दें, मैं जांच करवायेंगे ।

श्री गणेश प्रसाद यादवः पत्र निकला हुआ है, जांच कराने की क्या बात है ?

श्री मनोज कुमार यादव(मंत्री): माननीय सदस्य, पत्र को उपलब्ध करा दीजिये ।

अध्यक्षः इस पर पांच मिनट से ज्यादा हो चुका है । माननीय सदस्य, जनार्दन जी, एक पूरक आप भी पूछ लीजिये ।

टर्न-47/13.7.2000/
श्रीरमण/

(116)

सर्वश्री रामेश्वर प्रसाद एवं अन्य की ध्यानाकर्षण सूचना पर पूरक

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष महोदय, 9.10.91 को बिहार के मुख्य सचिव, अरूण पाठके ने तत्कालीन मुख्यमंत्री से क्रिमिनल केस करने का आदेश ~~था~~ मांगा था अध्यक्ष पर ?

अध्यक्ष : प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष पर ।

श्री मनोज कुमार यादव : महोदय, इसके संबंध में जानकारी हासिल करके उस पर कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : आपने जानकारी नहीं ली है माननीय मंत्री । पूरी तैयारी के साथ आना चाहिये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि सरकार के बिना आदेश के कोई भी बोर्ड का अध्यक्ष विदेश का भ्रमण कर सकता है ? अगर प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष भ्रमण किये हैं विदेश का तो उस पर सरकार ने कौन सी कार्रवाई करेगी ?

अध्यक्ष : विदेश का मामला इसमें निहित नहीं था लेकिन आपने सूचना दी है तो मंत्री जी इसको ग्रहण करेंगे और ~~आप/आप~~ देखेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन 91 में नामिनेट हुए थे, किस परिस्थिति में वे चेयरमैन बने हुए हैं ?

अध्यक्ष : उन्होंने जवाब दिया कि हम शीघ्र कार्रवाई कर रहे हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : माननीय मंत्री के गोल-मटोल जवाब देने से हमलोग संतुष्ट नहीं हैं, सदन संतुष्ट नहीं है । चेयरमैन, प्रदूषण बोर्ड 91 से आज तक लगातार चेयरमैन बने हुए हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री । उसमें अब नहीं । इनका जवाब दे दें ।

श्री ~~भाई वीरेन्द्र~~ मनोज कुमार यादव (मंत्री) : महोदय, जिन बातों का उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है, उन सारी बातों की जानकारी कर उस पर हमलोग कार्रवाई करेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : समय सीमा बताया जाय ।

अध्यक्ष : आप बैठिये न । ऐसा नहीं होता है । माननीय मंत्री ।

श्री मनोज कुमार यादव (मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, असेम्बली खत्म होने के बाद इस पर हमलोग जांच करके कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : रामेश्वर प्रसादजी, एक बात को जान लीजिये । ध्यानाकर्षण में जब आप पहली बार 3-4 प्रश्न पूछ चुके हैं तो फिर नहीं पूछ सकते हैं । नहीं कोई प्वाइंट आर्डर नहीं । सीखिये ।

टर्न-47/13.7.2000/
श्रीरमण/.

(1171)

सर्वश्री उमाशंकर सिंह, महेश्वर सिंह एवं अन्य (9) नौ सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (गृह (आरक्षी) विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री उमा शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्णियां कोर्ट परिसर में न्यायिक हिरासत की अवधि में दिनांक 19.4.2000 को श्री मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह, पूर्णियां जिला समता पार्टी अध्यक्ष की हत्या की गयी। इस हत्याकांड के किसी भी नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी करने में पुलिस पूर्णतः अक्षम साबित हो रही है तथा हत्याकांड को दूसरी ओर मोड़ने का कुचक्र चल रहा है।

अतः इसकी जांच सी0 बी0 आई0 से कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

डा0 रामचंद्र पूर्वे (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब 18 जुलाई को दे देंगे।

श्री रामधनी सिंह, स0वि0स0की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री रामधनी सिंह:- अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से कोचस एवं बसही होते हुए चौसा तक आने वाली सड़क अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है । यह कई वर्षों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त है । वित्तीय वर्ष 1999-2000 में इसके सासाराम से बसही तक 41 कि0मी0 की मरम्मति के लिए 3 करोड़ 61 लाख 97 हजार रुपये मात्र का प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ । इसमें से डिहरी डिवीजन की 24 कि0मी0सड़क की मरम्मति कार्य फरवरी-मार्च, 2000 में मात्र 1 करोड़ 80 लाख की लागत से ही पूरा करा लिया गया, जो प्राक्कलन की राशि से कम है । मरम्मति कार्य इतने घटिया स्तर का हुआ है कि तीन माह में ही सड़क मरम्मति पूर्व कि स्थिति में आ गई है । मैं मरम्मति कार्य में हुए घोर अनियमितता एवं निर्धारित मापदण्डों के उल्लंघन तथा शेष बचे 17 कि0मी0सड़क के मरम्मति कराने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

डा0रामचन्द्र पूर्वे (मंत्री):- महोदय, 18 जुलाई को इसका जवाब देंगे ।

श्रीमती रेणु देवी, श्री रामदेव महतो एवं अन्य दो सभासदों की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह (आरक्षी) विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्रीमती रेणु देवी:- अध्यक्ष महोदय, 26 जून, 2000 को दिन के लगभग दो बजे बेतिया नगर के युवा उद्यमी श्री रमेश तोदी का अपहरण कर लिया गया । अपहृत उद्योगपति अभी तक मुक्त नहीं कराये जा सके हैं । अपहरण फिरौती के लिए किया गया है । अपहरणकर्ता श्री तोदी को छोड़ने के एवज में बहुत बड़ी राशि की मांग कर रहे हैं । पूरे बेतिया क्षेत्र में भय, आतंक और तनाव का माहौल है । आम जनता अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही है । अपहृत श्री तोदी को शीघ्र बरामदगी एवं बेतिया क्षेत्र में कानून का शासन स्थापित करने की ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

डा0रामचन्द्र पूर्वे (मंत्री):- महोदय, इसका जवाब 17 जुलाई को दिया जायेगा ।

सर्वश्री प्रेम कुमार एवं अश्विनी कुमार चौबे, स0वि0स0की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री प्रेम कुमार:- अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य में अनुसूचित जाति जन-जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए ली गयी योजनाओं को धरातल पर उतारने में भी सक्षम नहीं हो पा रही है । सरकार इस वर्ग के लोगों के लिए

टर्न-48/राजेश/13.7.2000

छात्रवृत्ति, खेल-कूद, तकनिकी भत्ता के मद में वर्ष 1999-2000 में प्रावधान की राशि का 30 प्रतिशत भी बाँटने में सफल नहीं हो सकी है । अन्य पिछड़े वर्ग के ~~ख्रिस्~~ लोगों की स्थिति ज्यादा ही खराब है । वर्ष 1999-2000 के दौरान पिछड़े वर्ग के छात्रों के छात्रवृत्ति आदि के लिए गैर योजना मद में 1,20,80,000/-रुपये आवंटित किए गये थे इसमें 7,20,5800 की निकासी की गयी जिसमें मात्र 2,13,9900/- रुपये ही खर्च हो सके । राज्य में विकलांगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है । विकलांगों के मानदेय के लिए 47,91,000/- रुपये आवंटित किए गए, जिसमें 9,18,000 रुपये खर्च किए गए ।

अत: छात्र-छात्राओं को उपरोक्त मदों की राशि का भुगतान समय पर नहीं होने से हो रही असुविधा की ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री निर्मल तिर्की ‌(राज्यमंत्री):- महोदय, इसका 18 जुलाई को जवाब देंगे ।

टर्न-49/13.7.2000

सिन्हा ।

मानवीय मंत्री, स्वास्थ्य का मलेरिया के प्रसार एवं उससे संबंधित मौत के संदर्भ में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्न के आलोक में वक्तव्य ।

श्री शकुनी चौधरी (मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 4.7.2000 को "दैनिक जागरण" समाचार पत्र में माननीय पर्यटन मंत्री का मलेरिया से 40,000 आदिवासियों की मौत संबंधी स्वीकारोक्ति के प्रकाशन के संदर्भ में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्न के आलोक में सूचित करना है कि यह बात सही है कि राज्य में मलेरिया का प्रकोप है परन्तु समाचार-पत्र में दर्शा गयी सूचनायें तथ्य पर आधारित नहीं है । इस संदर्भ में मैं गत वर्ष तथा इस वर्ष का मलेरिया तकनीकी प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

वर्ष	संग्रहित रक्त पट	परीक्षित रक्त पट	धनात्मक रोगी	प्लाजमोडियम फैल्सीफेरम	मृत्यु संपुष्ट	संभावित	उपचारित	अभ्युक्ति
99	12,44,247	11,56,488	1,31,898	79,881	131	43	1,13,674	
2000	2,05,589	1,83,928	15,986	9,438	1	0	13,614	अप्रील

गोमिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोकारो का निरीक्षण दिनांक 25.5.2000 को मुख्य मलेरिया पदाधिकारी, बिहार, द्वारा की गयी । जनवरी से 25.5.2000 तक वाह्य रोगी पंजी में मात्र 1210 मरीज पंजीकृत हुए थे जिनमें से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई थी तथा उनमें से कुछ मरीज अन्य कारणों से ज्वर पीड़ित थे । सभी रोगियों को मलेरिया निरोधात्मक दवायें दी गयी थी ।

उपायुक्त, बोकारो द्वारा भी अक्तूबर, 2000 तक सिविल सर्जन, बोकारो द्वारा प्रतिवेदित तकनीकी आंकड़ा की सत्यता की संपुष्टि की गयी है ।

पूरे राज्य में मलेरिया के अतिप्रभावित 10 जिले घोषित किये गये हैं (पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गुमला, लोहरदगा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पलामू तथा गढ़वा)। इन वर्णित जिलों में से 9 जिले में मलेरिया निरोधात्मक कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से चलायी जा रही है । इस कार्यक्रम का नाम " उत्क्रमित मलेरिया नियंत्रण परियोजना" है । इस कार्यक्रम के तहत वर्णित जिलों में मलेरिया निरोधात्मक कार्य हेतु राशि का उपबंध भारत सरकार, विश्व बैंक के सहयोग से करती है तथा राशि का व्यय जिला समिति के माध्यम से की जाती है । समिति के अध्यक्ष संबंधित जिला के जिलाधिकारी/उपायुक्त होते हैं ।

टर्न-49/13.7.2000
सिन्हा ।

वर्त्तमान समय में राज्य के सभी जगहों में मलेरिया निरोधात्मक दवायें स्वास्थ्य उप-केन्द्र स्तर तक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । ग्राम स्तर पर 11,087 दवा वितरण केन्द्र तथा 8,974 ज्वर उपचार केन्द्र के माध्यम से भी मलेरिया निरोधात्मक दवायें उपलब्ध करायी जा रही है । इसके अतिरिक्त इस वर्ष माननीय विधायकगण तथा मंत्रीगण को भी दवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है ताकि वे अपने क्षेत्र भ्रमण के समय ग्रामीणों को दवा उपलब्ध करा सकें । इस आशय का एक पत्र मुख्य मलेरिया पदाधिकारी द्वारा सभी जिला मलेरिया पदाधिकारी तथा असैनिक शल्य चिकित्सक को लिखा गया है ।

मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में डी.डी.टी. का छिड़काव निम्न जगहों में प्रारंभ हो चुका है:

" हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरीडीह, नवादा रोहतास, कैमूर, गया तथा पश्चिमी चंपारण। "

शेष अन्य प्रभावित जिलों में छिड़काव प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है ।

भारत सरकार द्वारा मलेरिया रोगियों के उपचार हेतु क्लोरोक्वीन एवं प्राईमाक्वीन की गोली तथा जटील मलेरिया रोगियों के उपचार हेतु क्वीनीन इंजेक्शन की आपूर्ति की जाती है । वर्ष 1999-2000 में 3,50,00,000 क्लोरोक्वीन, 10,00,000 प्राईमाक्वीन (7.5 एम.जी.) तथा 13,00,000, प्राईमाक्वीन (2.5 एम.जी.) मांगी गयी थी जिसके विरूद्ध क्रमशः क्लोरोक्वीन 3,50,00,000, प्राईमाक्वीन (7.5 एम.जी.)-17,97,000 तथा प्राईमाक्वीन (2.5 एम.जी.) 11,50,000 की आपूर्ति की गयी । इसके अतिरिक्त 5,000 भायल क्वीनीन सूई की मांग की गयी थी जिसके विरूद्ध 10,000 क्वीनीन सूई की आपूर्ति की गयी ।

(क्रमशः)

श्री शकुनी चौधरी (क्रमश:) – वर्तमान वर्ष में जिलों को दवा की आपूर्ति करने के बाद (13.6.2000 तक) राज्य मुख्यालय भण्डार में दवा की स्थिति निम्न थी :–

क्लोरोक्वीन – 1,40,54,000 टैबलेट,
प्राईमाक्वीन (7.5एम0जी0)– 5,41,000
प्राइमाक्वीन (2.5एम0जी0)– 5,38,000 तथा
क्वीनीन सूई – 1,050

महोदय, माननीय मंत्री द्वारा मलेरिया रोगियों के उपचार हेतु लेरीगो की आपूर्ति की बात कही गयी। लेकिन लौरिगो सूई की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा नहीं की जाती है।

मलेरिया रोगियों के उपचार हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में दिशा- निदेश एवं निरोधात्मक दवाओं का डोज शिड्यूल निर्धारित किया जाता है जिसके आधार पर मरीजों की चिकित्सा की जाती है तथा वर्तमान समय में उपर्युक्त वर्णित दवाएँ पूरे भारतवर्ष में कारगर है।

श्री भोला प्रसाद सिंह – अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं, वह इतना बड़ा है कि उस जवाब को सभी माननीय सदस्यों के बीच बंटवा दिया जाये।

अध्यक्ष – बंटवा दें।

श्री शकुनी चौधरी (मंत्री)– वर्ष 1999-2000 में 1242 मे0टन डी0डी0टी0 की माँग भारत सरकार से की गयी थी जिसके विरुद्ध 600 मे0टन डी0डी0टी0 की आपूर्ति की गयी। वर्ष 2000 के लिए 1915 मे0टन डी0डी0टी0 की माँग की गयी है जिसमें 425 मे0टन0 डी0डी0टी0 आवंटित की गयी है, जो अभी तक अप्राप्त है।

महोदय, राज्य सरकार की तरफ से भारत सरकार को लिखा जा रहा है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि अभी एक हफ्ता पहले भारत सरकार द्वारा डी0डी0टी0, पोटाश और ब्लीचिंग पाउडर वगैरह: है, ये

भारत सरकार द्वारा भेजे जाते हैं। लेकिन बार-बार यह देखा जाता है कि उसमें बैच नम्बर नहीं है, उसमें स्पूरियस दवायें हैं, उसमें एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ नहीं है। ऐसी हालत में हमने कई जगह एफ0आई0आर0 कराये हैं और भारत सरकार को मैंने कहा है कि भारत सरकार बिहार को मारकेट नहीं समझे। मारकेट नहीं समझे। इसलिए कि हमारे यहां कुछ दवायें कि खपत नहीं हो सकती। यह दस करोड़ की आबादी वाला राज्य है और इसलिए हमारे पास जो दवायें भेजी जाये कम से कम अच्छी दवायें तो भेजें।

अध्यक्ष - दवाओं में बैच नम्बर तो रहना ही चाहिए।

श्री शकुनी चौधरी (मंत्री)- महोदय, बैच नम्बर भी नहीं रहता है। उसको भारत सरकार को लौटा दिया है, उसको नहीं लिया है, उसको प्राप्त नहीं किये हैं।

अध्यक्ष- कोई दूसरा सप्लायर होगा।

श्री शकुनी चौधरी (मंत्री)- अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं भारत सरकार के मंत्री से बात टेलीफोन पर किया है, और उन्होंने कहा है कि उस पर वे सख्ती से कार्रवाई करेंगे और उनकी तरफ से क्या कार्रवाई होती है, वे जानें।

मलेरिया रोग के नियंत्रणार्थ रोगियों की खोज एवं उनके उपचार को सुदृढ किया जा रहा है। माह जून, 2000 में "एन्टी मलेरिया माह" के अन्तर्गत जन-जागरण का कार्य किया जा रहा गया है। प्रभावित क्षेत्रों में रोग-वाही कीटों के नियंत्रणार्थ प्राथमिकता के आधार पर डी0डी0टी0 का भी छिड़काव कराया जा रहा है।

सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि मलेरिया की भयावह स्थिति से उत्पन्न नहीं हो तथा हर संभव तरीकों से मृत्यु दर में कमी लायी जा सके। विधान-सभा सत्र खत्म होते ही मैं स्वयं प्रभावित जिला का दौरा करूँगा और क्षेत्र के माननीय मंत्री, विधायक भी उस जिला में मौजूद रहने की कृपा करेंगे, यह मेरा विश्वास है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष – इस पर कोई वाद-विवाद नहीं होता है। अगर कोई सूचना हो तो माननीय मंत्री को भेज दीजियेगा ।

माननीय सदस्यगण, 36 निवेदनों की संख्या है। सभा की राय हो तो ये निवेदन विभाग को भेज दिये जायें ?

सदस्यगण – सहमति है।

अध्यक्ष – अब सभा की बैठक दिन शुक्रवार दिनांक 14-07-2000 के 10.00बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

= = = = =